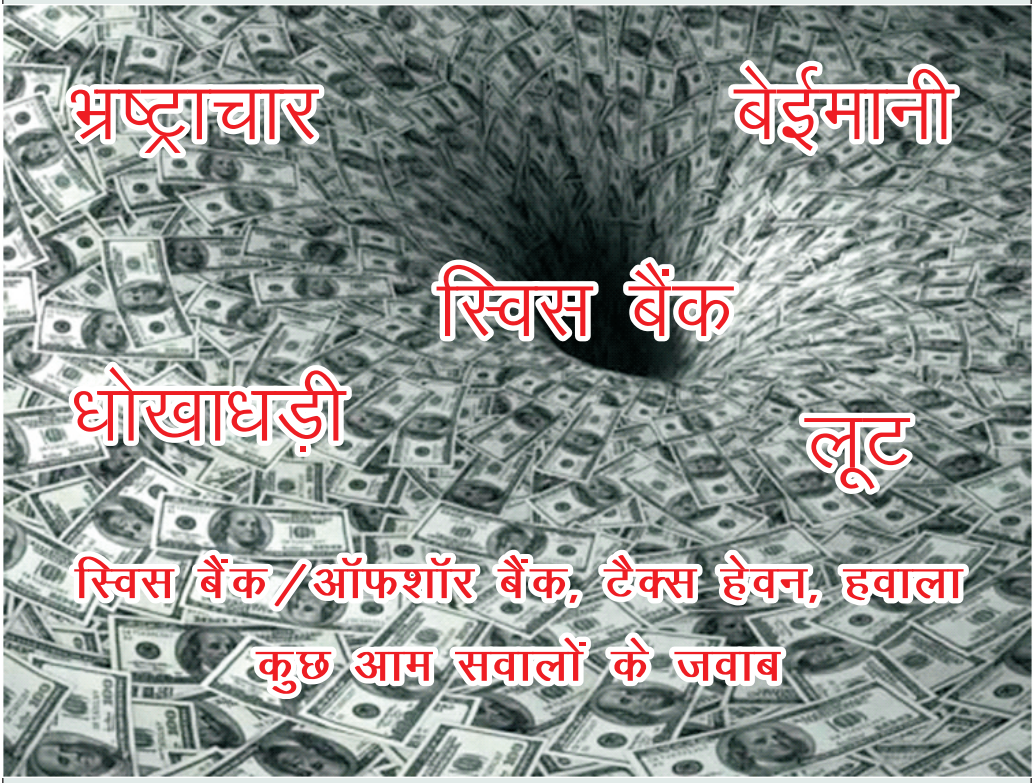

टैक्स हेवन टीम

द्वारा

सार्वजनिक दस्तावज़ों से संकलित

आर्थिक अध्ययन एवं योजना केन्द्र
सामाजिक विज्ञान संस्थान
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली–110067

टैक्स हेवन टीम

द्वारा

सार्वजनिक दस्तावज़ों से संकलित

आर्थिक अध्ययन एवं योजना केन्द्र
सामाजिक विज्ञान संस्थान
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली–110067

टैक्स हेवन टीम
अरुण कुमार
सौमेन चट्टोपाध्याय
अशू तिवारी
चैतन्य तलरेजा

अनुवाद
गणपत तेली

Swiss Bank/Offshore Banks, Tax Havens,
Hawala: Answers to Some Common Questions
By Tax Haven Team
2015
Centre for Economic Studies and Planning
School of Social Sciences
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067

भूमिका

पिछले पाँच वर्षों में भारत से स्विस बैंक और टैक्स हेवन में अवैध धन का जाना तथा हवाला जैसी गतिविधियाँ देश के लिए चिंता का विषय रही हैं। अलग–अलग व्यक्तियों, एजेंसियों के अनुसार बड़े पैमाने पर अवैध और काला धन विदेशों में जमा है– रामदेव के अनुसार 70 खरब (7 ट्रिल्यन) अमरीकी डॉलर, जीएफआई (ग्लोबल फाइनेंसियल इंटिग्रीटी) के अनुसार 462 अरब (बिलियन) अमरीकी डॉलर और सीबीआई के अनुसार 500 अरब अमरीकी डॉलर। जीएफआई ने 1948 से 2008 के बीच भारत से बाहर गये धन का हिसाब लगाया, उसी आधार पर सीबीआई ने 2008 से 2010 का अनुमान लगाया। GFI ने अपनी पद्धति भी सार्वजनिक की लेकिन CBI ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत से इस तरह बाहर जाने वाले अवैध (काले) धन को भारत की बढ़ती काले धन की अर्थव्यवस्था (ब्लैक इकॉनोमी) के साथ जोड़ा जाता है, जो 2013–14 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पचास प्रतिशत से भी अधिक या लगभग 900 अरब अमरीकी डॉलर है।

राजनीतिक दल विदेशों में जमा इस काले धन को भारत लाने का वादा कर यह प्रस्तावित कर रहे हैं कि उससे देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह कहा जा रहा है कि यदि विदेशों में जमा सारा काला धन भारत आ जाता है तो आने वाले बहुत सालों तक किसी टैक्स की आवश्यकता नहीं रहेगी या देश के हर गाँव को दस करोड़ रुपये (16 लाख डॉलर) मिलेंगे। उक्त दावे 2006 की एक अनाधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार स्विस बैंकों के खातों में 14 खरब अमरीकी डॉलर जमा हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट स्विस बैंक एसोसिएशन की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का अवैध धन अन्य सभी देशों के लोगों के जमा कुल धन से भी अधिक है।

लेकिन 2005 से 2008 के बीच की स्विस बैंक ऐसोसिएशन की किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। स्वयं ऐसोसिएशन ने ऐसे आंकड़ों की बात को खारिज़ किया है। यह भी सही नहीं लगता है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का धन अन्य सभी देशों के लोगों के कुल जमा धन से अधिक है क्योंकि पिछले बीस वर्षों में रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों से बड़े पैमाने पर धन बाहर गया है। हालांकि स्विटज़रलैण्ड अवैध धन की जमाखोरी के सबसे बड़े और चर्चित अड्डे के रूप में जाना जाता है लेकिन दुनिया भर में 70 से ज़्यादा ऐसे केन्द्र हैं। भारतीय अपने धन को ठिकाने लगाने के लिए उनमें से बहुतों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यदि केवल स्विटज़रलैण्ड में 14 खरब अमरीकन डॉलर भारत का कालाधन जमा है तो सभी टैक्स

हेवन का कुल धन इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है, जो संभव नहीं है।

भारत से बाहर ले जाया गया सारा काला धन वहाँ बैंकों में पड़ा नहीं रहता है, बल्कि उसे इस्तेमाल कर राउंड ट्रिपिंग के जरिए भारत वापस लाकर कई योजनाओं में उसे निवेश कर दिया जाता है। इसलिए विदेशी बैंकों में जमा धन भारत से बाहर गए कुल धन का एक हिस्सा मात्र ही है।

टैक्स हेवन टीम द्वारा 1948 से अब तक भारत से बाहर गए धन और उस पर अर्जित ब्याज का कुल योग 11 खरब अमरीकी डॉलर अनुमानित किया गया है। यह अवैध धन की अपोर्चुनिटी कॉस्ट है, इतना धन वहाँ जमा नहीं है और न ही उसे कोई मजबूत सरकार द्वारा वापस भारत लाया जा सकता है। इस टीम द्वारा अनुमातिक धन जीएफआई, वाशिंगटन द्वारा अनुमानित धन से कहीं ज़्यादा है क्योंकि जीएफआई द्वारा अपने अध्ययन में अवैध धन निकासी के कई तरीकों को अपनी गणना में शामिल नहीं किया गया है, जैसे व्यापार में गलत बिलिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग और ड्रग्स तस्करी जैसी गैर कानूनी गतिविधियाँ।

संक्षेप में, भारत से अवैध/काले धन के विदेशों में जमा होने और उसे वापस लाने के संबंध में कई गलत धारणाएँ फैली हुई हैं। दरअसल अवैध धन से जुड़े जटिल मुद्दों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। यही कारण हैं कि हमने इस पुस्तिका के प्रकाशन की योजना बनाई ताकि लोगों के सामने सरल रूप में सूचनाएँ लाई जा सकें। हमें उम्मीद है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे ताकि इस विषय पर एक तथ्यपरक सार्वजनिक बहस हो सके। हमारी यह परियोजना एसएनएफ, बर्जन, नार्वे के जरिए नार्वे सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है। हम टैक्स हेवन और इनके प्रभाव पर 2012 से नार्वे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त अध्ययन का हिस्सा हैं। हम इस सहायता के लिए अपना आभार जताते हैं। यह कार्य सुखमय चक्रवर्ती चेयर प्रोफेसर के सानिध्य में संपन्न हुआ है।

हम उन सभी विद्वानों और जानकारों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं, जिनसे हमने चर्चाएँ कीं लेकिन वे सार्वजनिक नहीं होना चाहते।

अरुण कुमार
टीम लीडर, टैक्स हेवन टीम,
सुखमय चक्रवर्ती चेयर प्रोफेसर
10 जुलाई, 2015

अनुक्रम

1.	स्विटज़रलैण्ड में गुप्त बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास	8
2.	'स्विस बैंक' और 'स्विस बैंकिंग' शब्दों के प्रचलित अर्थ और इनके द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएँ।	8
3.	"स्विस बैंक" कहे जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान और इकाइयाँ।	9
4.	'स्विस बैंकों' में किस प्रकार के खाते होते हैं?	9
5.	स्विस बैंकों में खाता खोलने और संचालित करने की आम पद्धति	9
6.	स्विस बैंकों और साधारण (नॉन स्विस) बैंकों के आपसी संबंध	10
7.	स्विस बैंक में आने वाले अवैध धन की लांडरिंग और उसे वैध करने की प्रक्रिया कितनी लंबी और कठिन है?	10
8.	स्विस बैंकों में जमा होने वाले अवैध धन का प्रकार	10
9.	क्या 'स्विस बैंक' खुद ही जमाओं का प्रबंधन (Solicit) करते हैं? यदि हाँ तो उनके क्या तरीके हैं?	11
10.	दुनिया में स्विस बैंक के अन्य सहयोगी कौन हैं?	12
11.	क्या अवैध धन के लेन–देन की स्थिति जानने के लिए 'स्विस बैंकिंग' और गोपनीयता के कानून वाले देशों (न्यायाधिकरण) से कोई मदद या सहयोग पाना संभव है?	12
12.	'स्विस बैंकिंग' प्रक्रियाओं में शामिल लोगों का सामर्थ्य और स्तर क्या है?	13
13.	यदि इस तरह के 80 जाने माने केन्द्र हैं तो क्यों आमतौर पर लोग स्विस बैंक की ही बात करते हैं?	13
14.	स्विस बैंकों की तरह ही काम करने वाले केन्द्रों की सूची	14
15.	स्विटजरलैण्ड लैण्ड लॉक्ड है, तो दुनियाभर में ऑफशॉर बैंकिंग और टैक्स हेवन कैसे उभरे?	17
16.	क्या जो बैंक स्विस बैंकिंग केन्द्र से संचालित नहीं होते हैं, वे भी अवैध धन को संग्रहित करते हैं और हाँ, तो कैसे?	18
17.	विभिन्न वित्तीय केन्द्रों को कौन नियंत्रित करता है और उन पर कौन–से कानून लागू होते हैं?	18
18.	ऑफशॉर टैक्स कन्सल्टन्ट्स की क्या भूमिका है और उनके द्वारा किस प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं?	19
19.	क्या जमाओं के संग्रहण में किसी बड़ी ऑडिट फर्म की कोई भूमिका होती है?	19
20.	ट्रासंफर प्राइसिंग और कर चोरी में इसकी भूमिका	19
21.	अवैध धन के लेन–देन के आंकड़े किस एजेंसी से प्राप्त किए जा सकते हैं?	20

22. कौन ज्यादा भ्रष्ट्रध्अपराधी है– अमीर विकसित देश, जो अवैध धन जमा करते हैं या पीड़ित गरीब देश, जहाँ लूट मचती है? 21
23. अमीर और शक्तिशाली लोगों तथा पूंजीपतियों के लिए 'स्विस बैंकिग का कॉस्ट बेनेफिट (Cost-Benefit) क्या है? 21
24. अमीर देशों के लिए स्विस बैंकिंग का कॉस्ट बेनेफिट क्या है? 21
25. उन देशों के नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जहाँ से यह काला धन बाहर चला जाता है? 22
26. अवैध धन की निकासी और लांडरिंग के सामान्य (आम) तरीकें क्या हैं? 23
27. अमेरीका जैसे विकसित देश मनी लांडरिंग विरोधी कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हाल–फिलहाल में वहाँ इस दिशा में क्या हुआ? 24
28. स्विटज़रलैण्ड में कुछ गंभीर अपराध ही दण्डनीय हैं। 26
29. अमरीका जैसे विकसित देशों में मनी लांडरिंग विरोधी कानूनों की सफलता की दर क्या है? 26
30. डबल टेक्सेशन अवोइडेन्स एग्रीमेंट के पीछे कौनसा सिद्धांत काम करता है? 26
31. टैक्स हेवन : अमीरों के स्वर्ग 27
32. हवाला क्या है? 28
33. क्या हवाला गैर–कानूनी है? 29
34. रेगुलर बैंक और टैक्स हेवन के ऑफशॉर बैंकों के बीच क्या अंतर है? 30
35. विकसित देशों में टैक्स हेवन का विस्तार। 30
36. शीर्षस्थ दस (टॉप 10) टैक्स हेवन और ऑफशॉर सेंटर (स्विस बैंकिंग केन्द्र) कौन से हैं, जो अवैध धन रखते हैं और कर चोरी में मदद करते हैं? 30
37. यदि सभी बड़े राजनेता, पूंजीपति और लोग काले धन से जुड़े हुए हैं तो फिर क्या सुधार हो सकते हैं? 32
38. भारत का भ्रष्ट्राचार निरोधक कानून क्या है? 32
39. भारत सरकार द्वारा विदेशों में स्थित स्विस बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए हाल में क्या कदम उठाए गए? 33

निष्कर्ष 33

शब्दावली 34
संदर्भ 40

बॉक्स की सूची

बॉक्स–अ : कुछ तथ्य : स्विस बैंकों के बारे में 16
बॉक्स–ब : आपराधिक गतिविधियों का आंकलन 18
बॉक्स–1 : ट्रांसफर प्राइसिंग का उदाहरण 20
बॉक्स–2 : मनी लांडरिंग कैसे काम करती है? 24
बॉक्स–3 : हवाला कैसे काम करता है? 29

स्विस बैंक/ऑफशॉर बैंक, टैक्स हेवन, हवाला : कुछ आम सवालों के जवाब

1 स्विटज़रलैण्ड में गुप्त बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहास

वित्तीय गोपनीयता की परंपरा स्विटज़रलैण्ड में 17वीं शताब्दी से तो मिलती ही है। पहले विश्वयुद्ध के कारण जब कई यूरोपीय मुद्राएँ डाँवाडोल हो गई थीं, तब स्थिर (कहने की आवश्यकता नहीं है कि अप्रभावित (Neutral) भी) स्विस मुद्रा ने जमाकर्ताओं को आकर्षित किया। राजस्व के नुकसान के बाद जब फ्रांस ने पेरिस स्थित एक स्विस बैंक पर छापा मारकर इसके खातों के नाम सार्वजनिक कर दिए, तो 1934 में एक कानून पास का स्विटज़रलैण्ड ने ऐसे सार्वजनिककरण को अपराध बना दिया। कुछ वर्षों बाद स्विस बैंकों ने जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति और नाजियों द्वारा लूटा हुए सोने– दोनों को जमा किया और बाद में नरसंहार पीड़ितों के लिए 1.25 अरब अमेरिकन डॉलर का एक कोष स्थापित किया। हाल के वर्षों में फिलीपीन्स के फर्डिनेन्ड मार्कोस से लेकर नाईजीरिया के सानि अबाचा तक ने अपने काले धन को छुपाने के लिए स्विस बैंकों का इस्तेमाल किया है।

स्विटज़रलैण्ड में बैंकिंग गोपनीयता 1930 के दशक में बैंक जमाकर्ताओं की जानकारी गोपनीय रखने के उद्देश्य से लागू की गई। बेसन (2004: 26–27) के अनुसार वह कानून मुख्य रूप से फ्रांस द्वारा फ्रांसीसी नागरिकों के स्विस बैंकों में रखे धन की जानकारी हासिल करने के प्रयासों के कारण बनाया गया था। स्विस सरकार स्विस बैंकों में रखे गए विदेशी धन के आर्थिक महत्त्व को अच्छे से जानती थी। उस समय के एक राजनयिक दस्तावेज के अनुसार स्विटज़रलैण्ड का इस मामले में फ्रांस के साथ सहयोग करने का कोई हित नहीं था जो स्विस बैंको की विदेशी जमाओं के उसके महत्त्वपूर्ण व्यवसाय पर कोई गंभीर असर डालता। तीन दशकों के बाद आज भी स्विटज़रलैण्ड का कानून गोपनीयता के उल्लंघन के लिए पचास हजार स्विस मुद्रा और छः महीने के जेल की सजा देता है।

2. 'स्विस बैंक' और 'स्विस बैंकिंग' शब्दों के प्रचलित अर्थ और इनके द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएँ।

उच्च स्तर की बैंकिंग गोपनीयता लागू करने के मामले में स्विटज़रलैण्ड मुख्य था। इसलिए यह 'स्विस बैंकिंग' की अवधारणा का पर्याय हो गया जिसका मतलब है, सभी तरह की गुप्त और अपारदर्शी बैंकिग। इस पुस्तिका में स्विस बैंकिंग शब्द का इस्तेमाल इस तरह की बैंकिंग के लिए किया गया है चाहे वह ऑनशॉर, ऑफशॉर हो या फिर किसी पूरी तरह कानून मानने वाले देश में हो।

3. "स्विस बैंक" कहे जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान और इकाइयाँ।

'स्विस बैंकिंग' केन्द्र बड़े और बेहतरीन बैंक/बीमा कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों का मेजबान या स्वर्ग है। उदाहरण के लिये–

- कैमन आइलैण्ड बैंकों का स्वर्ग है और अमेरीका सहित कई देशों के 90 प्रतिशत बैंकों के यहाँ मुख्यालय या मुख्य कार्यालय हैं।
- शिपिंग व्यवसाय में बाराम्यूडा सभी बड़े पूंजीपतियों की पहली पसंद है।
- अमेरिका का डेलावेर स्टेट सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियों का मुख्यालय हैं क्योंकि यह राज्य क्रेडिट संबंधी डिफाल्ट भुगतान पर असीमित ब्याज दर की लेवी अनुमोदित करता है।
- एमएनसी के गलत मूल्यीकरण, मुनाफा दबाने या धन को इधर–उधर काने के लिए टैक्स हेवन में सब्सिडिएरी और शैल कंपनियों का इस्तेमाल करती है।

4. 'स्विस बैंकों' में किस–किस तरह के खाते होते हैं?

निम्न प्रकार के खाते अलग–अलग उद्देश्य के लिए हैं:

चालू खाता (Current Account):
ये दैनिक लेन–देन के लिए होते हैं और इनमें थोड़ा ब्याज भी मिलता है।

बचत खाता (Saving Account):
ये बचत के लिए होते हैं। इनमें अच्छा–खासा ब्याज मिलता है और लेन–देन सीमित होता है।

नंबर्ड अकाउंट (Numbered Account):
इन खातों में अत्यधिक गोपनीयता होती है। स्विस बैंक इन खातों में नाम की जगह एक नंबर का इस्तेमाल करतें हैं। यह इतना गुप्त रखा जाता है कि कोई नहीं जान सकता है कि कौनसा खाता किसका है! इन खातों को अज्ञात खाते (Anonymous Account) भी कहते हैं।

5. स्विस बैंकों में खाता खोलने और संचालित करने की आम पद्धति

अलग–अलग संस्थानों के अपने नियम होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास जमा करने के लिए बहुत सारा धन है, तो कई बैंकों में वह अपनी सुविधा के अनुसार नियमों में

संशोधन की मांग भी कर सकता है।

6. स्विस बैंकों और साधारण (नॉन स्विस) बैंकों के आपसी संबंध

कई ऑनशॉर बैंकों के ऑफशॉर बैंकों तथा स्विस बैंकों के साथ साधारण व्यावसायिक संबंध हैं। उनके बीच धन के लेन–देन पर शायद ही कोई रोकटोक हो, चाहे वह धन वैध हो या अवैध। इसलिए ऑफशॉर/स्विस बैंकों में जमा काले धन को आसानी से वैध/सफेद बनाकर दुनिया की वित्त व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सकता है।

7. स्विस बैंक में आने वाले अवैध धन की लांडरिंग और उसे वैध करने की प्रक्रिया कितनी लंबी और कठिन है?

बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सलाहकारों, ऑडिट संस्थाओं, बैंकों, निजी इक्विटी संस्थाओं, वेंचर कैपिटलिस्ट आदि ने यह सुनिश्चित कर दिया कि सावधानी युक्त योजना से धन का रंग आसानी से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 करोड़ (एक अरब) रुपये काला धन है। यह धन हवाला के जरिए मनचाही जगह पर पहुँचाया जा सकता है। वहाँ इसका रंग बदला जा सकता है और किसी कंपनी या ट्रस्ट या किसी व्यक्ति या समूह द्वारा संचालित किसी संस्था में इसे लगाया जा सकता है। इसके बाद वह व्यक्ति अपने सलाहकारों की सलाह के अनुसार या उसकी अपनी समझ के अनुसार उस धन का निवेश कर सकता है। यहाँ तक कि इस धन को मूल देश (जैसे कि भारत) में एफडीआई या एफआईआई या निजी इक्विटी निवेश या वेंचर कैपिटल के रूप में वापस भी लाया जा सकता है।

8. स्विस बैंकों में जमा होने वाले अवैध धन का प्रकार–

इन बैंकों में मुख्य रूप से तीन (3) प्रकार से कमाया अवैध धन आता है–

(1) व्यावसायिक
(2) भ्रष्ट्राचार
(3) आपराधिक

व्यावसायिक गतिविधियों में लेन–देन के अनुसार अवैध धन होता है। गलत मूल्य निर्धारण (False Pricing), ज्यादा पैसे लेना (Overbilling) भुगतान कंपोजिशन (Composition of Payment) आदि के जरिए अवैध धन कमाने के कई तरीके हैं वे कुछ इस प्रकार के हैं:

- निर्यात–आयात की कम/ज़्यादा बिलिंग (Under Invoicing/Over Invoicing) और बेलेंस को विदेशों में जमा करवाना तथा मुख्य रक्षा या सिविल समझौतों के जरिए वह धन वापस लाना।
- विदेशों में की गई कमाई को यहाँ नहीं लाना।
- वर्षों पहले जब सोने का आयात अवैध था, तब सोने की तस्करी करना।
- विदेशों में अवैध धन का लेन–देन करना और उसे अपने देश में छुपाना, जैसे हवाला के जरिए धन भेजना।
- कलाकारों/मनोरंजन उद्योग द्वारा कमाया गया धन जिसे घोषित नहीं करना और विदेशों में जमा करना

दुनिया भर के लगभग सभी बड़े लेन–देन में और विकासशील देशों में छोटे लेन–देन में भी) **भ्रष्ट धन** मौजूद है। ओपेक रिसोर्स अलोकेशन और लाइसेंस परमिट प्रक्रिया में लिये गये कमीशन से भ्रष्ट्राचार के द्वारा अवैध धन आता है।

आपराधिक धन इन तीनों तरीकों में सबसे बड़ाा है। इसमें नशीले पदार्थों का व्यापार, मानव तस्करी, हथियारों का व्यापार (गन रनिंग), आतंकवाद आदि शामिल हैं। इन सबसे बड़ी मात्रा में अवैध धन कमाया जाता है। आज मानव व्यापार, मानव तस्करी, और हथियारों की तस्करी में लगा अनुमानित धन क्रमशरू 32 अरब, 35 अरब और 1 अरब अमरीकी डॉलर है। [http://www.havocscope.com/category/transnational-crime (21.07.2014), एक हालिया अनुमान के अनुसार भारत में ड्रग्स तस्करी, मानव व्यापार, सोफ्टवेयर पायरेसी, काउंटर फीटिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों में लगे कालाधन 69 अरब अमरीकी डॉलर अनुमानित किया गया है। [http://www.havocscope.com/tag/india (21.07.2014),

9. क्या 'स्विस बैंक' खुद ही जमाओं का प्रबंधन (Solicit) करते हैं?यदि हाँ तो उनके क्या तरीके हैं?

'स्विस बैंकिंग केन्द्रों' के बैंक, संस्थाएँ और संगठन कई तरीके अपनाते हैं– कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष। 'दी इकोनॉमिस्ट' जैसी सुप्रसिद्ध पत्रिका में ऐसे कई छोटे–छोटे विज्ञापन देखे जा सकते हैं। स्विटज़रलैण्ड में क्रेडिट स्विस (Credit Suisse) और यूबीएस (UBS) जैसे कुछ जाने–माने बैंक हैं जिनकी शाखाएँ और एजेंट दुनियाभर में फैले हुए हैं। धन प्रबंधन (वेल्थ मैनेजमेन्ट फंक्शन) के नाम पर ऐसी सेवाएँ प्रस्तावित की जाती हैं। अमरीका की सरकार ने अमरीकी नागरिकों की करचोरी में मदद के लिए 2009 में यूबीएस पर 7800 लाख अमरीकी डॉलर और हाल ही में क्रेडिट स्विस पर 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगाया।

सिटी बैंक (City Bank), जे.पी. मॉर्गन (J. P. Morgan), एचएसबीसी (HSBC), बार्कले (Barclays) जैसे बड़े बैंक भी ऐसी ही सेवाएँ देते हैं। इनके द्वारा ज़्यादा लाभ के लिए ऑनशॉर और ऑफशॉर दोनों ही सेवाएँ उचित तरीके से बनाकर दी जाती है। इसलिए जमाओं और ग्राहकों दोनों ही सभी उपलब्ध चौनलों द्वारा और जाहिर है कि सीधे भी आकर्षित किए जाते हैं। बैंक ऑफशॉर स्थिति का फायदा उठाते हुए न केवल अपना टैक्स बचाता है, बल्कि कई प्रकार की टैक्स अवोइडिंग स्कीम बनाकर अपने ग्राहकों को भी टैक्स चुराने में मदद करती है। बार्कले, एचएसबीसी, लोकस और आरबीएस ने मिलकर दुनियाभर में 3067 शाखाओं में से 1649 शाखाएँ टैक्स हेवन में बनाई। 2008 में दिवालिया होने वाले और बाद में दी नीदरलैण्ड्स सरकार द्वारा खरीदे गए फॉर्टिस बैंक की टैक्स हेवन में 700 शाखाएँ थीं।
[http://www-ethicalconsumer-org/ethicalreports/bankingindustrysectorreport/banksandtaxhavens.aspx (21/07/2014)]

10. दुनिया में स्विस बैंक के अन्य सहयोगी कौन हैं?

स्विस बैंकों के कई हिस्सेदार या सहयोगी हैं–

- ऑफशॉर कन्सल्टेंट्स
- धन प्रबंधन संस्थाएँ
- प्रतिष्ठित बैंकों के धन प्रबंधन विभाग
- अवैध कोष लाने वाले सहयोगी बैंक
- एआईजी जैसी इंश्योरेन्स कंपनियाँ जो कई शाखाएँ और ट्रस्ट खोलने की इच्छुक हैं, जो प्रश्न 9 में बताए गए निवेशकों के विशेष हितों के लिए काम करती हैं।
- पूंजीपतियों को कर योजना में मदद करने के लिए आवश्यक बड़े ऑडिट फर्म
- छोटे ऑडिट फर्म, जो बड़ी जमाओं से जुड़ सके।
- हवाला व्यापारी

11. क्या अवैध धन के लेन–देन की स्थिति जानने के लिए 'स्विस बैंकिंग' और गोपनीयता के कानून वाले देशों (न्यायाधिकरण) से कोई मदद या सहयोग पाना संभव है?

कुछ ही ऐसे अपराध हैं, जो स्विटज़रलैण्ड या अन्य टैक्स हेवन द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किए गए हैं। यहाँ तक कि आतंकवाद या नशीले पदार्थों जैसे अपराधों के लिए भी बेसिक रिस्पोंस पाने के लिए इच्छुक पक्ष को एक प्रार्थना पत्र के साथ सभी सबूत

और साक्ष्य जमा करने होते हैं। भारतीयों के जेहन में अभी हसन अली खान का मामला है। भारत सरकार यूबीएस में जमा धन को आतंकवाद और नशीले पदार्थों जैसे अपराधों के साथ सीधे जोड़ नहीं पाई इसलिए स्विस अधिकारियों से कुछ भी विस्तृत सूचना देने के लिए मना नहीं पाई।
सच कहें तो, 'स्विस बैंकिंग' और गोपनीयता के कानून वाले देशों से इस मामले में सहयोग या समर्थन हासिल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इनका निर्माण और विकास ही अनदेखे, अग्राह्य, अनियमित और बिना कर चुकाए धन को छिपाने, दबाने, पनाह देने, इधर–उधर करने और संचित करने के लिए किया गया है।

12. 'स्विस बैंकिंग' प्रक्रियाओं में शामिल लोगों का सामर्थ्य और स्तर क्या है?

स्विस बैंकिंग ने अच्छे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं निजी इक्विटी और ऑडिट फर्म को आकर्षित किया है। इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोटी तनख्वाह पर तेज तर्रार लोगों की नियुक्तियाँ की जाती है। इनमें से कई बड़ी कंपनियाँ अपने हितों के लिए कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदार बनाती है। आपसी सहयोग और फायदे के लिए अमीर और शक्तिशाली लोगों (राजनेताओं और नौकरशाहों भी) के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी काम करवाया जाता है। अमेरीका में एक ऐसे ही मामले में मि. बिर्केन्फेल्ड पकड़े गए क्योंकि वे ज्यूरिख और न्यूयॉर्क के बीच नियमित यात्राएँ किया करते थे। उन्हें सजा दी गई और यूएसबी बैंक जिसके लिए वे काम करते थे, पर 7800 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया।

13. यदि इस तरह के 80 जाने माने केन्द्र हैं तो क्यों आमतौर पर लोग स्विस बैंक की ही बात करते हैं?

हालांकि ठीक संख्या उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में चल रहे अवैध धन के लेन–देन में स्विटजरलैण्ड का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ के कई जाने–माने बैंक और निजी इन्वेस्टमेंट फर्म अवैध धन के प्रभावी रूपांतरण और प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। संक्षेप में, इस मामले में दूसरे बैंकों की तुलना में स्विस बैंकों की आज भी साख है।

14. स्विस बैंकों की तरह ही काम करने वाले केन्द्रों की सूची

पिछली गणना में दुनियाभर में ऐसे तकरीबन 80 केन्द्र थे– कुछ जाने–माने लेकिन अधिकतर अविश्वसनीय। सिंगापुर, हांगकांग, लदंन आदि विश्वसनीय हैं, तो कई ऐसे हैं जिनकी साख और विश्वसनीयता नहीं है। यहाँ तक कि अमरीका और इंग्लैण्ड भी

स्विस बैंकों के समान सेवाएँ देने वाले केन्द्र

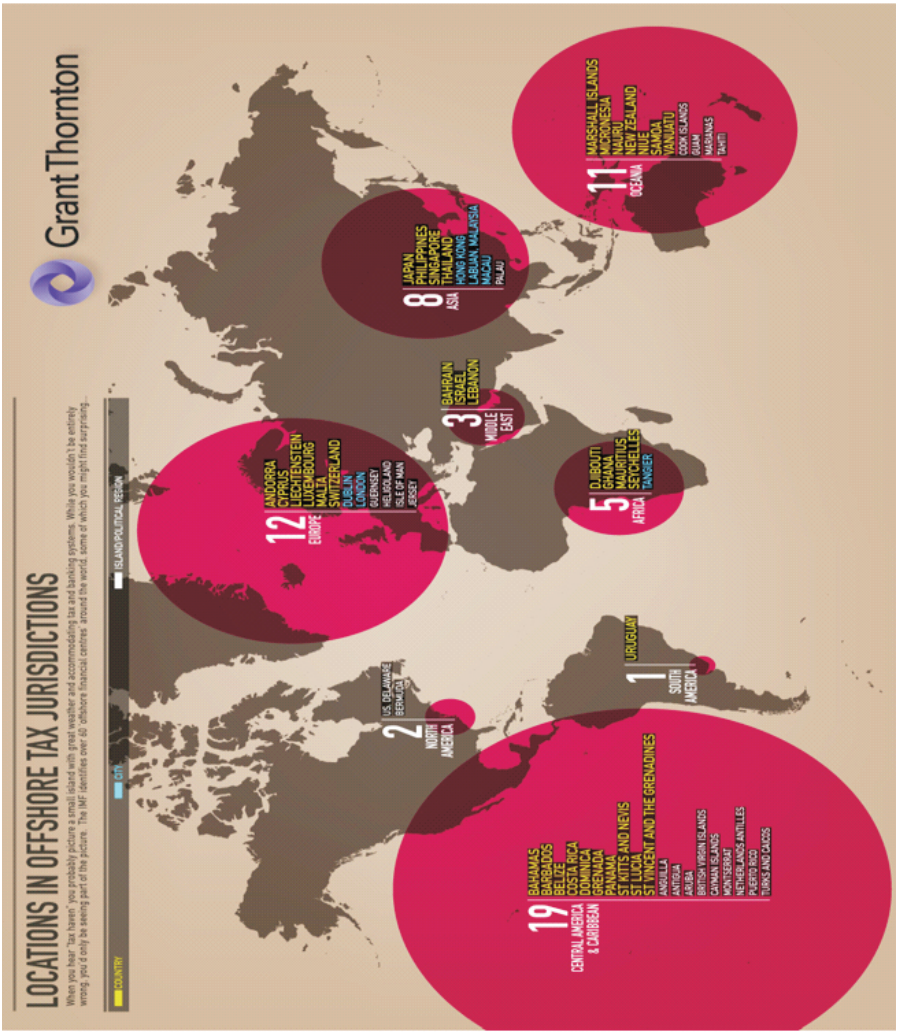

Source: http://www.grantthornton.co.uk/en/thinking/location_of_offshore_tax_juridictions_infographic (21/07/2014).

पालन ने 91 टेक्स हेवन की सूची दी है

टैक्स हेवन की सूची

क्र.सं.	टैक्स हेवन का नाम
1.	बहामास
2.	बाराम्यूडा
3.	कैमन आइलैण्ड्स
4.	गनज़ी (Guernsey)
5.	जर्सी
6.	माल्टा
7.	पनामा
8.	बारबेडोज़
9.	ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स
10.	साइप्रस
11.	आइल ऑफ मैन
12.	लिक्टनस्टाइन (Liechtenstein)
13.	नीदरलैण्ड एन्टाइल्स
14.	वेनुआटा
15.	गिब्रालटर
16.	हॉन्गकॉन्ग
17.	सिंगापुर
18.	सेंट विंसेंट एन्ड ग्रेनाडाइन्स
19.	स्विटज़रलैण्ड
20.	टर्क्स एन्ड काइकोस आइलैण्ड्स
21.	एंटीगुआ एण्ड बारबूडा
22.	बेलीज
23.	कुक आइलैण्ड्स
24.	ग्रेनाडा
25.	आयरलैण्ड्स
26.	लग्ज़म्बर्ग
27.	मोनाका
28.	नोरू
29.	सेंट कीट्स एंड नेवीस
30.	एंडोरा
31.	एंग्वीला
32.	बहरीन
33.	कोस्टारीका
34.	मार्शल आइलैण्ड्स
35.	मॉरीशस
36.	सेंट लूसिया
37.	अरुबा
38.	डोमिनिका
39.	लाइबेरिया
40.	समोना
41.	सिचलिस
42.	लेबनान
43.	नियु
44.	मकाओ
45.	मलेशिया (लबआन)

क्र.सं.	टैक्स हेवन का नाम
46.	मोन्सेरात
47.	मालदीव्स
48.	युनाइटेड किंगडम
49.	ब्रूनई
50.	दुबई
51.	हंगरी
52.	इज़रायल
53.	लेतविया
54.	मदयेरा
55.	नीदरलैण्ड्स
56.	फीलीपीन्स
57.	दक्षिण अफ्रीका
58.	टोंगा
59.	उरुग्वे
60.	यूएस वर्जिन आइलैण्ड्स
61.	संयुक्त राज्य अमेरिका
62.	अलदरनी
63.	अन्जुआन
64.	बेल्जियम
65.	बोथस्वाना
66.	कैंपियन इटालिया
67.	मिश्र
68.	फ्रांस
69.	जर्मनी
70.	ब्यूटेमाला
71.	हंडुरास
72.	आइसलैण्ड्स
73.	इंडोनेशिया
74.	इंगोसेतिया
75.	अर्दन
76.	मरियानास
77.	मलीला
78.	म्यांनमार
79.	नाईजीरिया
80.	पलाऊ
81.	क्योटोरिको
82.	रूस
83.	सान मरीनो
84.	साऊ तोमे ए प्रिसिंपे
85.	साक
86.	सोमालिया
87.	श्रीलंका
88.	ताइपे
89.	त्रिस्ते
90.	तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दन साइप्रस
91.	युक्रेन

(स्रोत: Palan et al, 2010: 41-44)

बॉक्स–अ

कुछ तथ्य : स्विस बैंकों के बारे में

- स्विस बैंक में रिटेल खाता खोलने के लिए 5000–10000 स्विस फ्रेंक और प्राइवेट खाता खोलने के लिए 200, 000 या इससे ज़्यादा स्विस फ्रेंक की आवश्यकता होती है।
  Source: http://www.swissprivacy.com/swiss.banking (07.08.2014)
- 26 प्रतिशत बाजार शेयर के साथ सीमापार प्राइवेट बैंकिंग में स्विस बैंक मार्केट लीडर हैं। (स्रोतः स्विस नेशनल बैंक का डेटा)
- स्विस बैंकों के प्रबंधन में कुल 5566 अरब स्विस फ्रेंक की राशि जिसमें से 51: विदेशी ग्राहकों का है। (स्रोतः स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी डेटा) http://www.swissbanking.org/en/facts_figues.htm (07.08. 2014)
- 2012 के अंत में स्विस बैंकों में पाकिस्तान के लोगों और कंपनियों द्वारा रखा गया धन 14410 लाख स्विस फ्रेंक भारत के 14210 लाख स्विस फ्रेंक से ज़्यादा हैस्रोतःhttp://timesofindia.indiatimes.com/india/pakistan-money-in-swiss-banks-higher-than-indias-Switzeland-data/aticleshow/20699190.cms (07.08.2014)
- अनुमान है कि टैक्स हेवन बीस लाख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का केन्द्र हैं (Palan et al 2010: 05) जिनमें कई प्रकार के ट्रस्ट, म्युचुअल फंड, हेज (hedge) फंड और बीमा कंपनियाँ शामिल हैं।
- टैक्स हेवन के क्षेत्राधिकार में सभी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेंडिंग का लगभग 50 प्रतिशत और एफडीआई का 30 प्रतिशत पंजीकृत है। (वही)
- कैरीबिया का एक छोटा–सा द्वीप कैमन आईलैण्ड दुनिया का पांचवाँ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र है। (वही)
- दुनिया में अवैध धन की सबसे बड़ी शरणस्थली स्विटजरलैण्ड है। 2007 में स्विटज़रलैण्ड में विदेशियों की जमा धन राशि 31 खरब अमरीकी डॉलर थी जो वैश्विक वित्त संकट के बाद 2009 में घटकर 21 खरब अमरीकी डॉलर रह गई। (Shaxon, 2012: 61)
- 2011 के जीएफआई के अनुमान के अनुसार 2000–2008 के बीच 18 प्रतिशत की वृद्धि दर वाले विकसित देशों ने 2008 में अवैध धन के मामले

में 12 खरब अमरीकी डॉलर का नुकसान झेला। इसकी तुलना में कुल विदेशी सहायता 123 अरब अमरीकी डॉलरी थी।
(स्रोतः http://www.globalissues.org/article/35/foreign-aid-development-assistance (21.07.2014)

टैक्स हेवन में जमा वैश्विक धन के बारे में कुछ अनुमान

संयुक्त राज्य अमरीका के लिए ऑफशॉर बैंकिंग के जरिए हर साल करीब 100 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान है (Gravelle 2013:01)। 2005 में टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुमान के अनुसार कर चोरी से सभी देशों को लगभग 225 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान होता है, जिसमें 110 खरब अमरीकी डॉलर ऑफशोर धन शामिल है। यह दुनिया का एक चौथाई धन है और अमरीका के जीएनपी के लगभग बराबर है। (Shaxon 2012: 26) लेकिन यदि हम इन बैंकों में रखे हालिया धन का अनुमान लगाए तो यह लगभग 210 खरब से 320 खरब अमरीकी डॉलर होगा। राजस्व नुकसान का आंकड़ा भी इसी अनुपात में ऊपर गया (Gravelle 2013: 23-24)। इन आंकड़ों में उद्योगपतियों के गलत मूल्य निर्धारण से गया शामिल नहीं है।

टैक्स हेवन विशिष्टताओं वाले देश के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अमरीका में डेलावेर, नेवाडा और वायोमिंग राज्यों में जहाँ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कम है, ब्याज कर मुक्त है और लेन–देन तथा व्यवसाय संचालन सरल है। डेनमार्क, आइसलैण्ड, इज़रायल और मडेरा द्वीप (पूर्तगाल) भी टैक्स हेवन माने जाते हैं। टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा जारी सूची के अनुसार मलीला, सोमालिया, मध्य और एशिया में लबुआन (मलेशिया, तेल अबीव और ताइपेय तथा यूरोप में बेल्जियम, डबलिन, इंगूशेटिया, मडेरा, सार्क, ट्रिस्के, टर्किश रिपब्लिक और नार्दन साइप्रस और फैंकफर्ट (Gravelle 2013: 07)।

15. स्विटजरलैण्ड लैण्ड लॉक्ड है, तो दुनियाभर में ऑफशॉर बैंकिंग और टैक्स हेवन कैसे उभरे?

हालांकि प्राचीन यूनान के समय से ही कराधान (टेक्सेशन) मौजूद है लेकिन बीसवीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इसे व्यवस्थित तरीके से और सख्ती से लागू किया। पहला ऑफशॉर बैंक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चौनल आइलैण्ड पर पनपा। इसने रुपयों को कर से बचाने का अवसर उपलब्ध करवाया। इसलिए पहले ऑफशॉर बैंक

का नाम चैनल आइलैण्ड पड़ गया। बाद में ऑफशॉर बैंकिंग के आइलैण्ड में होने की परंपरा ही चल पड़ी। बहमास, कैमन आइलैण्ड, और साइप्रस इसके उदाहरण हैं। छोटे देशों के लिए कम या बिना टैक्स के इस तरह पूंजी को आकर्षित काने का लोभ बढ़ता चला गया। इनमें से कई तो आइलैण्ड क्या, समुद्र के करीब भी नहीं हैं। वे उनके गोपनीय कागजों और आय पर कम करों के कारण टैक्स हेवन के रूप में जाने गए।

16. क्या जो बैंक स्विस बैंकिंग केन्द्रों से संचालित नहीं होते हैं, वे भी अवैध धन को संग्रहित करते हैं और हाँ, तो कैसे?

हाँ, वे अवैध धन को वैध (Sanitize) करने के लिए "स्विस बैंकिंग सिस्टम" के बैंकों और सहयोगियों के रूप में काम करते हैं।

बॉक्स–ब
आपराधिक गतिविधियों का आंकलन
दी इकोनोमिस्ट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े आठ अपराध हैं–ड्रग्स की तस्करी (2012 में वैश्विक राजस्व 320 अरब अमरीकी डॉलर), काउंटफ्रेट और पाइरेटेड सामान (2012 में वैश्विक राजस्व 250 अरब अमरीकी डॉलर), मानव तस्करी (वैश्विक राजस्व 32 अरब अमरीकी डालर), जंगली जीवों की तस्करी (वैश्विक राजस्व 19 अरब अमरीकी डॉलर), अवैध तेल व्यापार (2012 में वैश्विक राजस्व 11 अरब अमरीकी डॉलर), अवैध लॉन्जिंग (2012 में वैश्विक राजस्व 10 अरब अमरीकी डॉलर), मानव अंग (2012 में वैश्विक राजस्व 6000 लाख अमरीकी डॉलर)

17. विभिन्न वित्तीय केन्द्रों को कौन नियंत्रित करता है और उन पर कौन–से कानून लागू होते हैं?

स्विटज़रलैण्ड, सिंगापुर आदि बहुत अमीर और महत्त्वपूर्ण संप्रभु देश हैं, लेकिन दूसरे केन्द्र दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं–

- कैमन, जर्सी, आइलसमैन आदि आइलैण्ड राष्ट्र पूर्ण रूप से ब्रिटेन, नीदरलैण्ड जैसे विकसित देशों के नियंत्रण एवं न्यायाधिकरण में हैं।
- डेलावेर जैसे इन्क्लेव अमरीका जैसे शक्तिशाली देशों के हिस्से हैं। इस तरह के क्षेत्रों का उद्देश्य यह होता है कि इनके होने से अवैध धन देश के बाहर नहीं जाता है और मुनाफा देश में ही रहता है।

तरह के क्षेत्रों का उद्देश्य यह होता है कि इनके होने से अवैध धन देश के बाहर नहीं जाता है और मुनाफा देश में ही रहता है।
संक्षेप में, ये केन्द्र पूरी तरह से विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा सुरक्षित, नियन्त्रित और प्रोत्साहित हैं।
इसके अलावा मॉरिशस, सिंगापुर और माल्टा जैसे कुछ छोटे देश भी हैं, जिनके विकसित देशों के साथ ऐसे संबंध नहीं हैं।

18. ऑफशॉर टैक्स कन्सल्टन्ट्स की क्या भूमिका है और उनके द्वारा किस प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं?

इनकी मुख्य भूमिका धन इधर–उधर करने या निकालने की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करवाते हुए अपने ग्राहक को उसके निवेश पर बेहतर रिटर्न दिलवाने में मदद करवाने की है।
ये निर्धारित शुल्क पर समस्त लेन–देन के बारे में सलाह देते हैं और मदद करते हैं। दूसरे क्षेत्रों की तरह वे एक या दोनों पक्षों से फीस ले सकते हैं।
ऐसे धन के उचित प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में ट्रस्ट, कंपनियों साझेदारियों आदि जैसी वित्तीय व्यवस्थाओं/इकाइयों की सरंचना में बहुत–सी जटिलताएँ होती हैं। ऑफशॉर कन्सल्टेंट ऐसी औपचारिक प्रबंधन की सेवाएँ भी देती हैं।

19. क्या जमाओं के संग्रहण में किसी बड़ी ऑडिट फर्म की कोई भूमिका होती है?

बड़ी ऑडिट फर्म की कई शाखाएँ होती हैं। ऑडिट मुख्य है लेकिन कन्सल्टेंसी और सलाह के रूप में वे कई दूसरी सेवाएँ भी देती हैं। कुशल और लागत प्रभावी कर योजना इनमें से एक महत्त्वपूर्ण सेवा है। इसी तरह प्रोजेक्ट कंसेप्शन, प्रोजेक्ट फाइनेसिंग, जैसी सेवाएँ भी ये फर्म देती हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं लेकिन 'स्विस बैंकिंग सिस्टम' के ऑडिट फर्म सहयोगियों और कन्सल्टेंसी फर्म में मेल–जोल होता है।

20. ट्रासंफर प्राइसिंग और कर चोरी में इसकी भूमिका

ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है जब कोई कंपनी कम टैक्स वाले देश में पंजीकृत अपने सहयोगियों से बिक्री में कम धन लेती है और खरीददारी के समय अधिक कीमत अदा करती है, इससे कम टैक्स क्षेत्र की कंपनी उत्पादन और लागत की शर्तों से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करती है। जब किसी एक मल्टी एंटीटी कंपनी के अलग–अलग

विभाग अपना मुनाफा दर्ज़ करते हैं, तो वे एक ही कंपनी के अलग–अलग विभागों में भी ट्रासंफर प्राइसिंग करते हैं। इसके द्वारा मुनाफे को कम टैक्स वाले देश में स्थानांतरित किया भी जाता है। गूगल, एप्पल, अमेजन, फेसबुक, याहू और स्टारबक्स सभी पर चतुराई से मुनाफा स्थानांतरित करने के आरोप लग चुके हैं (Gravell 2013:11)।

बॉक्स–1

ट्रांसफर प्राइसिंग का उदाहरण

मान लीजिए 'क' कंपनी 100 रुपये का सामान खरीदती है और दूसरे देश में अपनी सहयोगी कंपनी 'ख' को 200 रुपये में बेच देती है, जो उसे खुले बाजार में 400 रुपये में बेचती है। यदि इसे 'क' कंपनी ने सीधे बेचा होता तो उसे 300 रुपये का मुनाफा होता लेकिन इसे 'ख' के जरिए बेचकर अपना मुनाफा 100 रुपये तक ही सीमित कर लिया और 'ख' को पर्याप्त मुनाफा कमाने का अवसर दिया। 'क' और 'ख' के बीच का लेन–देन खुला और बाज़ार द्वारा नियमित नहीं होता है। इस तरीके से 200 रुपये का मुनाफा 'ख' कंपनी के देश में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सामान एक कीमत (ट्रांसफर प्राइस) पर ट्रांसफर किया जाता है, जो मनचाहा (200 रुपये) होता है न कि बाज़ार भाव (400) रुपये)।

वोडाफोन इंग्लैण्ड की कंपनी है। इसकी भारतीय शाखा हाल में इसकी मॉरिशस शाखा को 8519 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर बेचने के कारण खबरों में थी। भारत के आयकर विभाग के अनुसार इसका बाज़ार मूल्य 53,775 रुपये प्रति शेयर था। इस तरह से यह ट्रांसफर प्राइसिंग/अंडर प्राइसिंग के जरिए कर चोरी का मामला है।

21. अवैध धन के लेन–देन के आंकड़े किस एजेंसी से प्राप्त किए जा सकते हैं?

ऐसे कई संगठन और संस्थाएँ हैं (संदर्भ सूची देखें)। टैक्स जस्टिस इंटरनेशनल (टीजेआई) जैसे थिंक टैंक हैं, जो अपने स्वयं के मूल्यांकन एवं अनुमान करते हैं। भारत उन देशों में शामिल है, जो अवैध तरीके से बहुत–सा धन खो देते हैं। वाशिंगटन स्थित ग्लोबल फाइनेसियल इंटिग्रिटी ने धन निष्कासन का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन किया है। [Kar and Smith, 2008, 2010: www.gfip.org (21-07-2014)] आजादी के बाद भारत से बाहर गए धन का अपोर्चुनिटी कोस्ट कम से कम करीब 500 अरब अमरीकी डॉलर है [CBI Director, http://archive.indianexpress.com/news/blackmoney-indians-have-

stashed-over-500-bn-in-banks-abroad-says-sbi-911524(21.07.2014)] और हमारे अनुमान से अधिकतम 11 खरब अमरीकी डॉलर है।

22. कौन ज्यादा भ्रष्ट्र/अपराधी है– अमीर विकसित देश, जो अवैध धन जमा करते हैं या पीड़ित गरीब देश, जहाँ लूट मचती है?

यह सब जानते हैं कि किसी भी अपराध में शामिल सभी समान रूप से दोषी होते हैं। अवैध धन का संग्रह करने, उसे इधर–उधर करने, उसकी जमाखोरी करने और उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी समान रूप से दोषी हैं। फिर भी ज्यादा दोष 'स्विस बैंकिंग सिस्टम' को दिया जाना चाहिए जो कि लोगों और पूंजीपतियों को अवैध धन कमाने और जमा करने का विकल्प देकर कई तरह के अपराधों के लिए उकसाता है। इस तरह की किसी शरणस्थली के अभाव में अपराधियों को अपने अपराध का सबूत छिपाने में कठिनाई होगी, जिससे पूरी दुनिया में अपराध कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह के सुरक्षित स्थान के अभाव में पूंजीपतियों को भी अपना मुनाफा छिपाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं मिलेगा। इसी तरह का प्रभाव भ्रष्ट समझौतों पर भी होगा।

इस तरह से यह कहा जा सकता है कि अवैध धन की धनी राजधानी और टैक्स हेवन ज्यादा दोषी है।

23. अमीर और शक्तिशाली लोगों तथा पूंजीपतियों के लिए 'स्विस बैंकिग का कॉस्ट बेनेफिट (Cost-Benefit) क्या है?

स्विस बैंकों के कारण अमीर और शक्तिशाली लोग बहुत फायदे में रहते हैं। पूंजीपति और लोग इस तरीके से जायज टैक्स चुकाने से बच जाते हैं। उचित लांडरिंग के बाद ऑफशॉर खातों में आने वाली राशि अमीरों को उपलब्ध हो जाती है।

ऑफशॉर खातों में आने वाला धन निश्चित लांडरिंग के बाद अमीरों के लिए उपलब्ध हो जाता है। अमीर देशों की स्थिति उन साहूकारों की तरह है जो गरीब कर्जदारों के भाग्य पर नियन्त्रण रखने में सफल हैं। साहूकारों के पास कर्ज़दारों की संपत्ति पर कब्ज़ा होता है, ब्याज वसूलना होता है और इसी प्रकार से किसी भी स्थिति में संपत्ति के पूरे नियंत्रण की शक्ति भी होती है।

स्विस बैंकों में मौजूद धन अन्य बैंकों या प्राइवेट इक्विटी संस्थानों को कई प्रकार के अग्रिम (एडवांसेज) भुगतान में बदल दिया जाता है। चूंकि इस धन के निष्कासन के कारण विकासशील देश पूंजी खो देते हैं। इसलिए वे लगातार कमजोर होते जाते हैं। अमीर एवं शक्तिशाली देशों की बेहतर क्रेडिट रेटिंग और कम ब्याज पर 'स्विस बैंकों' या इसके संगठनों द्वारा ज्यादा पूंजी आकर्षित करने से गरीब देशों के बल पर अमीर

वर्ग शक्तिशाली होता जाता है।
अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए अवैध धन स्थानांतरण की कीमत नाम मात्र की होती है। उचित जगह पर संसाधन ले जाने के कारण वे कम श्रम में अच्छा परिणाम पाते हैं। डेवोस जैसी जगह उनमें से बेहतरीन को हर साल वैश्विक गरीबी और अन्य समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उकसाती है और उनके हितों का आधार भी पूरी तरह से जानती है।

24. अमीर देशों के लिए स्विस बैंकिंग का कॉस्ट बेनेफिट क्या है?

गैर–यूरोपीय और विकासशील देशों से अरबों–खरबो डॉलर अवैध और काला धन यूरोपीय और विकसित देशों में आता है। असल में, कैरीबीयन द्वीप और एशिया–अफ्रीका के अधिकांश गोपनीयता रखने वाले क्षेत्रों में जमा किया गया काला धन कई रास्तों से तत्काल पश्चिम देशों द्वारा शासित क्षेत्रों में स्थानांतरित का दिया जाता है (Baker, 2005)। जीएफआई के अनुसार 2000 से 2008 औसतन करीब 725 से 800 अरब अमरीकी डॉलर विकासशील देशों से विकसित देशों में पहुँचा है (Kar and Curcio, 2011)। अमीर और शक्तिशाली देशों में आने वाला यह विशाल धन उन्हें गरीब और विकासशील देशों को दबाने, नज़रअंदाज करने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह अवैध धन विकासशील देशों के जीवन स्तर और उपभोक्ता व्यव्य को बढ़ाता है तो साथ ही विकासशील देशों की कठिनाई और गरीबी को भी बढ़ाता है। टैक्स हेवन के कारण विकासशील देशों को टैक्स का भी नुकसान होता है। [http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2011/12/GFI_2010_IFF_Update_Report-web.pdf (21.07.2014)]

सामान्यतः अमीर देशों के पास निम्न तरीकों से धन आता है:

- नशीले पदार्थों की तस्करी
- वैश्विक अपराधों में वृद्धि
- आतंकवाद
- भ्रष्टाचार में वृद्धि
- गरीबी में वृद्धि
- अनेक राज्यों और देशों की असफलता का प्रभाव
- विश्व के कई हिस्सों में असंतोष
- पूंजीवादी अपराधीकरण

25. उन देशों के नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जहाँ से यह काला धन बाहर चला जाता है?

बेशकीमती पूंजी खोने वाले देशों के सामने कई समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं:

- गरीबी तथा असमानता में वृद्धि
- सरकारी कर राजस्व में कमी
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में कमी
- आर्थिक वृद्धि की निम्न दर
- निवेश के स्तर में गिरावट
- नीतियों की असफलता
- महंगाई की उच्च दर
- कर्ज़ के बोझ में वृद्धि और अन्य।

26. अवैध धन की निकासी और लांडरिंग के सामान्य (आम) तरीकें क्या हैं?

जैसा कि प्रश्न 7 में बताया गया है, हवाला और अवैध तरीकों से धन स्थानांतरण आसान है। चयनित खाते और पसंदीदा केन्द्र में एक बार जमा हो जाने के बाद वह मनचाहे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद रीयल एस्टेट, राउंड ट्रिपिंग सभी तरह के संभावित निवेश के विकल्प भी उपलब्ध हो जाते हैं।

मनी लांडरिंग के प्रारंभिक (प्लेसमेंट) चरण पर व्यक्ति अपनी अवैध संपति वित्त व्यवस्था में लाता है। यह बड़ी राशि को अनेक छोटी राशियों में बांटकर सीधे किसी बैंक खाते में जमा कर या फिर कई मौद्रिक दस्तावेज़ (जैसे चेक, मनीऑर्डर आदि) खरीद कर बाद में इकट्ठा किसी अन्य स्थान पर खातों में जमा करवा दिया जाता है। यह प्रकिया 'स्मर्फिंग' कहलाती है।

धन के वित्त व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद दूसरा चरण (लेयरिंग) प्रारंभ होता है। इस चरण में लांडरर को धन को उसके स्रोत से दूर करने के लिए कई रूपांतरण और स्थानांतरण करता है। उस धन को इन्वेस्टमेंट इन्स्ट्रूमेंट की खरीद–बिक्री के जरिए व्यवस्थित किया जा सकता है। या लांडरर आसानी से धन को दुनियाभर के विभिन्न बैंकों के खातों के जरिए धन को व्यवस्थित कर सकता है। इस उद्देश्य से बड़े पैमाने पर छोटे खातों का इस्तेमाल उन इलाकों में ज्यादा प्रचलित हैं जो मनी लांडरिंग विरोधी जाँच–पड़ताल में सहयोग नहीं करते हैं। कुछ मामलों में लांडरर सामान या सेवाओं के भुगतान के ऊप में धन देता है, इससे वह वैध दिखाई देता है।

[http://www.bstdb.org/about-us/key-doccuments/corporate-documents/Anti_fraud_corruption_and_money_laundering_policy.pdf (04-06-2014)]

बॉक्स–2
मनी लांडरिंग कैसे काम करती है?

<u>प्लेसमेंट</u>
एक व्यक्ति (अ) अवैध हथियारों के व्यापार, ड्रग्स तस्करी, इनसाइडर ट्रैडिंग, पाइरेटेड सामान, मानव तस्करी एवं अन्य अवैध व्यापारों से बहुत सारा रुपया कमाता है। 'क' देश में 'अ' बहुत से महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करता है। 'अ' अपना काला धन उसी रूप में नहीं रख सकता है क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का डर रहता है इसलिए वह दूसरे भ्रष्ट व्यक्ति 'ब' से संपर्क काता है जो एक बैंकर है। 'ब' की मदद से 'अ' फर्जी कंपनियों और शैल कंपनियों के नाम से खाते खुलवाने के लिए कुछ लोगों को लगाता है। इन फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंकों में बड़ी राशि (निर्धारित सीमा में) और कुछ छोटी राशि जमा की जाती है।

<u>लेयरिंग</u>
इस तरीके से 'अ' अपनी अवैध संपत्ति सिस्टम में लगा देता है। राशि जमा काने के बाद 'अ' 'ग' देश में विदेशी कंफनी द्वारा लाये गए सामान से संबंधित दस्तावेज़े दिखाता है। उन दस्तावेज़ों के आधार पर बैंक सामान के विदेशी वितरकों के नाम पर धन स्थानांतरित कर देता है। इस तरीके से, धन एक देश (टैक्स हेवन) की पहली शैल कंपनी से अन्य देश (टैक्स हेवन) की शैल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और अन्य कंपनियाँ बंद कर दी जाती

<u>इंटिग्रेशन</u>
सभी जटिल प्रक्रियाएँ पूरी कर लेने के बाद अब 'अ' पूरे धन को एक साथ करना चाहता है। बहुत आसानी से वह अपने देश की फर्जी कंपनियों के लिए विदेशी फर्जी कंपनियों से कर्जा लेकर वह सारा धन अपने देश में ला सकता है। एंटीटी पेपर 'अ' को धन इस्तेमाल करने का हक देती है।
1991 में इडी द्वारा पकड़े गए एक बहुत बड़े मनी लांडरिंग के मामले में यही पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, नरीमन पोइंट ब्रांच मुंबई शामिल था।

27. अमेरीका जैसे विकसित देश मनी लांडरिंग विरोधी कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हाल–फिलहाल में वहाँ इस दिशा में क्या हुआ?

मनी लांडरिंग विरोध मुख्य रूप से वित्त और कानूनी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसका मतलब मनी लांडरिंग से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य नियामक इकाइयों का वैध नियंत्रण है। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर मनी लांडरिंग विरोधी कानून महत्त्वपूर्ण हो गया और यह यूएस प्रेटिओट एक्ट (PATRIOT ACT) का हिस्सा बन गया।
Source: http://en.wikipedia.org/wikki/Antimoney_laundering_software(04.06.2014)

आज दुनिया के अधिकांश वित्तीय संस्थानों और कई गैर–वित्तीय संस्थानों के लिए किसी भी संदेहास्पद लेन–देन को चिन्हित कर संबंधित देश की वित्तीय गुप्तचर इकाई को रिपोर्ट करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी भी बैंक के लिए संदेहास्पद लेन–देन ग्राहक की पहचान का प्रमाणीकरण और लेन–देन पर निगरानी रखनी होगी। इसके लिए कई वित्तीय संस्थान संदेहास्पद व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी जुटाने के लिए विशेष सोफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और सी–6 जैसी कंपनियों की सेवाएँ लेते हैं। मनी लांडरिंग से संबंधित युनाइटेश स्टेट्स फेडरल लॉ बैंक सिक्रेसी एक्ट 1970 के तहत लागू किया गया है, जो फिलहाल एन्टी मनी लांडरिंग एक्ट से संशोधित है। बहुत से लोग एन्टी मनीलॉन्डरिंग लॉ (AML) और एन्टी टेरेरिस्ट फाइनेंसिंग (ATF) में भ्रमित हो जाते हैं। अमेरीका के बैंक सीक्रेसी एक्ट के तहत मनी लांडरिंग और टेरेरिस्ट फाइनेसिंग उसे कहा जाता है, जब वित्त संस्थान अमरीका की सरकारी एजेंसी फाइनेंसियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (Fin Cen) को संदेहास्पद गतिविधि (Suspicious Activity Report-SAR) के बारे में बताते हैं। AML और ATF के प्रभावी लागूकरणधक्रियान्वयन के लिए अमरीकी सरकार वित्तीय संस्थानों को AML और ATF मामलों के लिए यूएस पेट्रिएट एक्ट की धारा 314 (B) के तहत एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि, कानून के अनुसार वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की गोपनीयता सुरक्षित रखनी होती है, इसलिए इन वित्तीय संस्थानों द्वारा धारा 314 (b) के तहत सहयोग का पालन प्रायरू नहीं किया गया। इस स्थिति से निपटने के लिए AML और ATF कर्मियों द्वारा इस वैश्विक सहयोग को प्राप्त करने के लिए अधिकांश देशों के गोपनीयता कानूनों के अनुसार युनाइटेड क्राइम्स एलिमिनेशन नेटवर्क (UCEN) की स्थापना की गई।
गतिविधियों की प्रकृति और व्यापकता के अनुसार विभिन्न देश विभिन्न कार्यवाही चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 10,000 अमरीकी डॉलर या इससे अधिक की जमा पर एक CTR (करेंसी ट्रांसेक्शन रिपोर्ट) आवश्यक है। यूरोप में 15,000 यूरो पर और स्विटज़रलैण्ड में 25,000 स्विस फ्रैंक पर यह आवश्यक है। भारत में किसी भी बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थ के लिए दस लाख रूपये से अधिक के लेन–देन पर वित्त मंत्रालय की गुप्तचर इकाई को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

[http://fiuindia.gov.in/furnishing-cashtransac.htm (06.08.2014),
कुछ देशों में सीटीआर की कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में मनी लांडरिंग के संदेह पर SAR करना आवश्यक है जबकि स्विटज़रलैण्ड में SAR तभी किया जा सकता है जब वह गतिविधि प्रभावित की जा सकती है। भारत में भी बैंकिंग कंपनी, वित्तीस संस्थान या एजेंसी द्वारा ऐसी परिस्थिति में वित्तीय गुप्तचर इकाई द्वारा संदेहास्पद लेन–देन रिपोर्ट करना आवश्यक है। [http://fiuindia.gov.in/furnishing-suspicious.htm (06.08.2014),
परिणामस्वरूप, अमेरीका में हर रोज हज़ारों SAR दर्ज की जाती है, जबकि स्विटज़रलैण्ड में यह संख्या बहुत कम है। ड्रग्स और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय एक वेबसाइट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मनीलांडरिंग सूचना नेटवर्क चलाता है, जिससे मनी लांडरिंग विरोधी मुद्दों पर नीतिगत सुझाव और सरकारों व निजी क्षेत्रों के लिए बेहतर कार्यक्रम उपलब्ध कराती है।

28. स्विटज़रलैण्ड में कुछ गंभीर अपराध ही दण्डनीय हैं।

व्यावहारिक रूप से दुनियाभर में कमाया गया अवैध धन संबंधित केन्द्र या देश के अपराध कानून की सीमा से परे के क्षेत्रों में लगाया जा सकता है।

29. अमरीका जैसे विकसित देशों में मनी लांडरिंग विरोधी कानूनों की सफलता की दर क्या है?

अमरीका में महज 0.01 प्रतिशत।
यह दर कम इसलिए है कि क्योंकि न किसी वैध गतिविधि में उस धन या लेन–देन को छिपाया जा सकता है। गोपनीयता और प्रमाण के अभाव में स्विटज़रलैण्ड में यह असंभव है कि ऐसे मामलों में आपराधिक गतिविधियों के लिए किसी पर आरोप तय हों। अन्य टैक्स हेवन भी अवैध धन के लेन–देन का स्वागत करते हैं और किसी भी कार्यवाही के प्रति उदासीन रहते हैं। कुछ द्वीपीय देश तो अवैध धन के लेन–देन को संभव बनाने के लिए कानून भी बदल देते हैं। इसलिए इन केन्द्रों में किसी का दंडित हो पाना असंभव है।

30. डबल टेक्सेशन अवोइडेन्स एग्रीमेंट के पीछे कौनसा सिद्धांत काम करता है?

कई देशों ने आपसी संधियों के जरिए दोनों देशों में आय कर को सीमित करने के समझौते किए हैं। डबल टेक्सेशन ट्रीटी का मतलब प्राय: ऐसा समझौता होता है

जिसके तहत कोई टैक्स एक ही देश में (दोनों में नहीं) में लगाया जाता है। लेकिन यह घोषित धन के बारे में हैं न कि उस काले धन के बारे में जो दोनों देशों में अघोषित है।
यह सामान्य बात सभी जानते हैं कि बहुत सी कंपनियों के मुख्यालय एक देश में होते हैं और कई देशों में उसकी शाखाएँ चलती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 'क' कंपनी भारत में अपनी उत्पादन और वितरण युनिट खोलना चाहती है। इसका एशिया का मुख्यालय मॉरिशस, कैमन आइलैण्ड या किसी अन्य टैक्स हेवन में हो सकता है। और उसके अधीन भारत और चीन में इसकी शाखाएँ या इकाइयाँ संचालित हो सकती है। डबल टेक्सेशन ट्रीटी के अंतर्गत यह कंपनी (जब तक भारत और मॉरिशस के बीच डबल टेक्सेशन ट्रीटी है) आय और कोर्पोरेट टैक्स भारत या मॉरिशस दोनों में से किसी एक जगह अदा करने का विकल्प चुन सकती है। यह बता सकती है कि यह कंपनी अपने कर मॉरिशस में चुकाएगी। इस विकल्प से यह कंपनी भारत में अपना मुनाफा बढ़ा सकती है। चूंकि भारत में आयकर तीस प्रतिशत है और मॉरिशस में सिर्फ एक प्रतिशत है तो यह अपने सारे मुनाफे की गणना मॉरिशस में कर भारत में टैक्स चुकाने से बच जाएगी। यह तरीका बहुत अधिक प्रचलन में है और फर्जी मूल्य, गलत घोषणा, फ्रेंचाइजिंग फीस, प्रबंधन फीस आदि वाणिज्यिक लेन–देन के जरिए अवैध और काले धन के प्रवाह का कारण है।
किसी व्यक्ति को अपने देश से अनिवासी बनाकर स्विस बैंकिंग न्यायाधिकरण का निवासी बनने की अनुमति देने वाली संधि की शर्तों के अनुसार टैक्स में राहत मिलती है।
ऐसी संधियों के द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों में निवेश विदेशी स्रोतों से चैनलाइज होता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भारत में FDI और FII में सबसे ज्यादा हिस्सा मॉरिशस का है। अनुकूल टैक्स संधियों के कारण सिंगापुर भी गति पकड़ रहा है। इन संधियों का नुकसान यह भी है कि किसी एक देश में जमा किया गया अवैध धन स्विस बैंकिंग केन्द्रों के जरिए सेनिटाइज करके वैध निवेश के रूप में वापस लाया जा सकता है, उन देशों में जिनके साथ डबल टेक्सेशन ट्रीटी है। इसे राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है।

31. टैक्स हेवन : अमीरों के स्वर्ग

ये क्षेत्र (जगह/देश/द्वीप) कर के मामलों में व्यक्तियों (विदेशियों) और व्यवसायों को अनुकूल अवसर एवं शर्ते उपलब्ध कराते हैं। ये आकार, प्रकार, समय, नियमों आदि के अनुसार अलग–अलग हो सकती हैं। ये पुराने द्वीप या मुख्य विकसित देश या शहर हो भी हो सकते हैं।
दूसरे शब्दों में ये टैक्स हेवन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो यहाँ किए गए लेन–देन पर कम टैक्स लगाते हैं या टैक्स लगाते ही नहीं है और अपने जमाकर्ताओं तथा निवेशकों

की गोपनीयता भी सुनिश्चित करते हैं। इन टैक्स हेवन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति वहां रहता है या टैक्स के फायदे के लिए उस देश से बाहर व्यवसाय करता है। वे विदेशी कर संबंधी संस्थाओं को बहुत ही कम सूचना देते हैं या सूचन देते ही नहीं है।

ये टैक्स हेवन मुख्य धारा के देशों की टैक्स व्यवस्था और टैक्स प्रक्रिया व नियमों की तौहीन करते हैं। परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक लोगों की पीड़ा के बल पर वैश्वीकरण के फायदे ग्लोबल इलीट और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में हो जाते हैं। टैक्स हेवन वित्तीय वैश्वीकरण के केन्द हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, बल्कि यह आधुनिक व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा है। हालांकि वे वैधानिक क्षेत्र हैं और वे अपनी संप्रभुता से अपनी कर दर निर्धारित करते हैं और सबसे ज़्यादा निवेशकों की गोपनीयता, जो काले धन को छिपाने के लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। ये न केवल कंपनियों और अमीरों के टैक्स बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टैक्स (कर) योजना के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि वे महत्त्वपूर्ण वित्त केन्द्रों के रूप में उभरे हैं।

32. हवाला क्या है?

'हवाला' शब्द का अर्थ है– भरोसा। यह दक्षिण एशिया में पुराने ज़माने में पनपा और आज दुनिया भर में प्रचलित है। ये प्रायः मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा धन स्थानांतरित करने का पारंपरिक तरीका था।

हालांकि यह धन स्थानांतरण का लोकप्रिय तरीका है लेकिन अब यह गैर कानूनी है। यह विश्वास और भरोसे से चलता है। पुराने जमाने में हवाला का काम करने वाले लोग हवालादार नाम से जाने जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह धन भेजने के लिए निकट परिवार के लोगों का इस्तेमाल करते थे। एक हवालादार दूसरे शहर के हवालादार को सूचित कर संबंधित व्यक्ति को नियत भुगतान करने के लिए कहता है। एक निश्चित समय के बाद दोनों हवालादार अपना हिसाब करते हैं कि किसके कहने पर किसने कितना धन चुकाया और कितना पाया तथा बाद में अपना हिसाब करते हैं। यह तरीका अपराधियों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि हवालादार व्यक्तियों के लेन–देन का हिसाब नहीं रखते हैं, इससे धन भेजने वाले और पाने वाले की पहचान छुप जाती है। हवाला के जरिए न केवल सार्वजनिक नीति के खिलाफ अवैध धन का लेन देन किया जाता है बल्कि कर चोरी, मनी लांडरिंग, हथियारों के व्यापार, बाल शोषणध्यौन शोषण और आतंकवाद आदि अपराधों को सरकारों की पहुँच से बाहर रखने के कारण यह व्यवस्था आज आधुनिक बैंकिंग के जमाने में भी प्रचलित है। भारत में यह व्यवस्था बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत से पहले विकसित हुई थी। इसे अंडरग्राउंड बैंकिंग भी कहते हैं।

बॉक्स–3
हवाला कैसे काम करता है?

हवाला अवैध धन को बाहर भेजने या भारत लाने का एक वैकल्पिकध्समानांतर तरीका है। इसमें भारत से विदेशी मुद्रा के बदले विदेश में मुद्रा का लेन–देन होता है। यह दो तरफा लेन–देन आवश्यक है क्योंकि विदेशों में भारतीय मुद्रा स्वीकृत नहीं है और बदल भी नहीं सकती। चूंकि यह हस्तांतरण अवैध है, इसलिए हवाला रुपये को अमरीकी डॉलर में बदलता है। हवाला से भारत में भी एक शहर से दूसरे शहर में हवाला चलता है, धन स्थानांतरित किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए एक भारतीय 'अ' विदेश में 'क' को रुपया भेजना चाहता है। इसके लिए 'अ' हवालादार (1) से संपर्क करता है जो भारतीय रुपया लेता है। अब रुपये को डॉलर में बदलने के लिए अवैध डॉलर की ज़रुरत पड़ेगी। यह काम हवालादार (2) से होगा, जो 'क' के देश में रहता है। उसी देश में 'स' रहता है, जो भारत में 'ब' को धन भेजना चाहता है। इसलिए 'स' हवालादार (2) के पास जाता है और धन स्थानांतरण के लिए डॉलर देता है। इससे आवश्यक अवैध डॉलर आता है, जो रुपये के बदले में दिया जाएगा। दोनों हवालादार इसे अपने खाते में दर्ज़ करते हैं। अब हवालादार (2), जिसे 'स' से डॉलर मिले 'क' को निर्धारित डॉलर दे देगा। हवालादार (1), जिसे रुपया मिला, 'ब' को धन दे सकता है। दोनों हवालादार अपने अवैध धन की आपूर्ति का हिसाब रखते हैं और लेन–देन करते हैं। यहाँ केवल हिसाब लिखने की व्यवस्था होती है और इसमें यदि जरूरत हुई तो फाइनल लेन–देन किया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय मुद्रा भारत में ही रहती है और 'अ' से 'ब' के पास चली जाती है और अमरीकी डॉलर विदेश में ही रहती है तथा 'स' से 'क' के पास चली जाता है। इस सेवा के लिए हवालादार निश्चित कमीशन भी लेते हैं। चूंकि बहुत से लोग विदेशों में पैसा भेजना चाहते हैं और बहुत से लोग विदेशों से भारत पैसा भेजना चाहते हैं, इसलिए दो तरफा लेन–देन की आवश्यकता नहीं होती है।

33. क्या हवाला गैर–कानूनी है?

हाँ, आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों की स्थापना के बाद हवाला को गैर–कानूनी घोषित कर दिया गया है। चूंकि धन हस्तांतरण की यह व्यवस्था पुरानी है और किसी कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह कई सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गई है। नियम–कानूनों के साथ–साथ दूसरी चुनौती यह भी है कि इस व्यवस्था का

दुनिया भर में काले धन को वितरित करने और आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अन्य गैर–कानूनी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेण्ट एक्ट– FEMA 2000 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट PMLA 2002– दो मुख्य कानून हैं, जो ऐसे धन हस्तांतरण को गैर–कानूनी ठहराते हैं।

34. रेगुलर बैंक और टैक्स हेवन के ऑफशॉर बैंकों के बीच क्या अंतर है?

टैक्स हेवन के बैंक ठीक उसी तरह की सभी सेवाएँ देते हैं, जो ऑनशॉर बैंक देते हैं लेकिन साथ–साथ कुछ निम्न विशेष सेवाएँ भी देते हैं–

- एस्टेट (संपदा) योजना
- धन प्रबंधन
- भरोसा बनाना
- संस्थान बनाना
- अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सहयोग निर्माण
- निजी निवेश बैंकिंग और
- नंबर्ड अकाउंड (खाते)

ये बैंक रेगुलर बैंकों की तुलना में कम ब्याज देते हैं और कई बार उनके पास जमाधन के प्रबंधन के लिए शुल्क भी लेते हैं।

35. विकसित देशों में टैक्स हेवन का विस्तार।

गोपनीय बैंक खातों को खोलने एवं संचालित करने वाला पहला देश स्विटज़रलैण्ड था। इसकी सफलता के बाद ब्रिटेन, नीदरलैण्ड जैसे कई देशों ने अपने उपनिवेशों में ऐसे विशेष केन्द्र स्थापित किये जो उनके देश से दूर हो सकते थे। इस तर्क को ध्यान रखकर कई द्वीप (आईलैण्ड्स) गोपनीय बैंकिंग केन्द्र बन गए। एक समय के बाद, अमेरीका जैसे देशों ने अपने ही क्षेत्राधिकार में ऐसे विशेष क्षेत्र बनाए, जहाँ ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

36. शीर्षस्थ दस (टॉप 10) टैक्स हेवन और ऑफशॉर सेंटर (स्विस बैंकिंग केन्द्र) कौन से हैं, जो अवैध धन रखते हैं और कर चोरी में मदद करते हैं?

<u>बेल्जियम</u>

आश्चर्यजनक, लेकिन बहुत सालों से बेल्जियम कंपनियों के लिए कम कर दर की

व्यवस्था चला रहा है और देश के बैंक खातों की जानकारी किसी को नहीं देता है। हालांकि बाद में इसने अपनी नीति बदली।

बाराम्यूडा
यह उन अमरीकी कंपनियों की पसंदीदा जगह है जो अपना मुख्यालय इस टैक्स हेवन में स्थानांतरित कर देती है और अपना बाकी का सारा काम–काज उच्च कर वाली जगह (अमरीका) में ही रहने देती है।

कैमन आइलैण्ड्स
यह छोटा द्वीप गोपनीयता और कम दर के कारण दुनिया के सबसे बड़े वित्त केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा कहा जाता है कि शैल कंपनिया स्थापित करने के लिए ''वहाँ दरवाज़ों पर नेम प्लेट लगाए जाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है।"

डेलावेर (यूएसए)
यह भी टैक्स हेवन के रूप में चिन्हित है। यह ऐसा राज्य है, जहाँ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कम हैं, ब्याज पर कर नहीं है और गोपनीयता से लेन–देन होते हैं।

हॉन्गकॉन्ग
यह भी एक अन्य पुराना उपनिवेश है, जो आज टेक्स हेवेन है। यहाँ पर कम का दर, कड़ी गोपनीयता और व्यापार का बड़ा केन्द्र अवैध धन को छिपाने में मददगार होते हैं।

आयरलैण्ड
इसने यूरोप के लिए कम कर वाले प्रवेश द्वार के रूप में अपने आप को स्थापित किया। लंबे समय तक सब ठीक चलता रहा। 2008 के बाद की मंदी तक, जब एक के बाद एक बैंक दिवालिए होते गये तब ऐसी स्थिति आई कि सभी नियमों–कानूनों को ताक पर रख दिया गया। अपने कर बचाने के लिए अमेजन, एप्पल सहित कई कंपनिया इसका इस्तेमाल करती है।

लग्ज़म्बर्ग
यह एक छोटी–सी उग्र राज्य सत्ता है जो यूरोपीय संघ के अंदर ही कर गोपनीयता रखती है, जिससे इसके अपने कम कर वाले ढाँचे के जरिए बड़े पैमाने पर धन आता है।

सिंगापुर
यह सब कुछ करता है, यह स्विटजरलैण्ड की तरह ही है। ऐसा लगता है कि सिंगापुर UBS में नया S है।

स्विटज़रलैण्ड
टैक्स हेवन में सबसे बड़ा और चर्चित नाम और कई मामलों में टैक्स हेवन का पुरोधा। इसने कर चोरों की मदद के लिए (न कि यहूदी शरणार्थियों की मदद के लिए, जैसा कि इसका दावा है) बैंकिंग गोपनीयता की शुरुआत की और कुछ वर्षों पहले यह इस मामले में अभेद्य माना जाता था। अब OECD के दबाब से थोड़ा सा बदलाव आया है।

लंदन
दुनिया के तमाम गोपनीय नेटवर्क का मुख्य केन्द्र– मुख्य काम बड़े पैमाने पर आने वाले अज्ञात धन को लंदन में लगाना।

37. यदि सभी बड़े राजनेता, पूंजीपति और लोग काले धन से जुड़े हुए हैं तो फिर क्या सुधार हो सकते हैं?

टैक्स जस्टिस नेटवर्क/ग्लोबल फाइनेंसियल इंटीग्रीटी और ऐसे ही अन्य एनजीओ अब बराबरी की बात कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय ढाँचा अमीर और बेईमान लोगों तथा देशों की ओर झुका हुआ है।
अब समय आ गया है कि शांति, न्याय और समता की पुनर्स्थापना के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जाए। कनाडा जैसे देशों में कुछ अच्छी शुरुआत भी हुई है, जहाँ अपराध देश में हो या बाहर– एक जैसा बर्ताव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ को महत्त्व देना होगा।
इस सामाजिक कैंसर को मिटाने के लिए तंबाकू विरोधी अभियान की तर्ज पर "स्विस बैंकिंग" और इसके सहयोगियों के बुरे प्रभावों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन जागरण करना होगा।
भारतीय संदर्भ में अरुण कुमार (1999) ने आरटीआई, राजनीतिक और न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने और बैंकिंग गोपनीयता को समाप्त करने जैसे कई सुझाव दिए हैं, जिनके अभाव में धन को चोरी छिपे बाहर ले जाया जाता है।

38. भारत का भ्रष्ट्राचार निरोधक कानून क्या है?

भ्रष्ट्राचार का मतलब है किसी भी क्षेत्र में देश के नियमों और कानूनों को तोड़ना। हालांकि प्रचलित समझ के अनुसार इसका अर्थ सत्ताधारी लोगों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा की गई गैर–कानूनी गतिविधियाँ भी शामिल होती है। दुर्भाग्य से समाज में इसकी जड़े बहुत गहरी हैं।
भारत सरकार ने प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया। इसका उद्देश्य भारत में सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों से भ्रष्ट्राचार मिटाना था। यह कानून

सार्वजनिक सेवक / कार्य, भ्रष्ट्राचार के अंतर्गत आने वाले काम और दोषियों के लिए सजा परिभाषित / निर्धारित करता है।

39. भारत सरकार द्वारा विदेशों में स्थित स्विस बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए हाल में क्या कदम उठाए गए?

2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक विशेष जाँच दल (SIT) का गठन किया गया। इस एसआईटी को स्विस बैंक से बात कर भारतीय खातेदारों के नाम सार्वजनिक किए जाने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही, इसे धन के इस निष्कासन को रोकने के सुझाव देने के लिए भी कहा गया।
भारत सरकार ने कई देशों के साथ कई तरह की डबल टेक्सेशन अवोइडेंस एंग्रीमेंट (डीटीएए) भी किए हैं। 2009 में भारत ने ऐसे 78 समझौते किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित सूचना का आदान–प्रदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो ताकि डीटीएए प्रभावी हो, भारत सरकार ने 28 देशों के साथ दोबारा बातचीत की और साथ ही 17 नए देशों के साथ बातचीत शुरू की। स्विटज़रलैण्ड के साथ भी कर संधि में संशोधन कर 17 जून 2011 को हस्ताक्षर किए। (भारत सरकार, 2012)
यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यह डीटीएए सिर्फ घोषित आय पर ही लागू होता है जबकि अवैध रूप से कमाए गए काले धन इस संधि के दायरे से बाहर ही रह जाता है। और जैसा कि रुडोल्फ एल्मर (फ्रंटलाइन, जून 27, 2014: 22–23) ने बताया कि भारत और स्विटज़रलैण्ड का शासकवर्ग वाकई में उन छिपे रास्तों को नहीं रोकना चाहेगा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और अमीर लोगों के लिए खुले हैं।

<u>निष्कर्ष</u>
यह दस्तावेज़ टैक्स हेवन और अवैध या कालेधन के विदेशों में जमा जाने के जटिल मामले से जुड़े कुछ सवालों का जवाब है, जो न केवल विकासशील देशों पर बुरा प्रभाव डाल रही है, बल्कि कुछ मायनों में विकसित देशों को प्रभावित कर रही है। विकसित देश पूंजी के आगमन से फायदे में तो रहते हैं लेकिन उन्हें अपने समाज में अपराधों की वृद्धि, आतंकवाद का भय और एक हद तक राजस्व के नुकसान के खतरे भी रहते हैं। यह विश्व समुदाय (अमीरों और पूंजीपतियों के नहीं) के हित में है कि इस समस्या को तत्काल सुलझाया जाय। चूंकि यह एक वैश्विक परिघटना है, इसलिए इसके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है।
दुर्भाग्य से यह समस्या राजनीतिक भी है क्योंकि कई देशों के शासक वर्ग के लोग अपने धन प्रबंधन के लिए स्विस बैंकों में खाते रखते हैं। नेता लोग जानते हैं कि यह व्यवस्था कैसे काम करती है और इसे कैसे रोका जा सकता है लेकिन वे अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण इस समस्या के समाधान के लिए कुछ ठोस उपाय नहीं करते हैं।

इसलिए, दुनिया के हर एक देश में राजनीतिक दबाव बनाना आवश्यक है।
पहला काम यह करने की ज़रुरत है कि विकसित देशों के इन टैक्स हेवन केन्द्रों के गोपनीयता के कानूनों को खत्म कर देना चाहिए और दूसरा उनके क्षेत्राधिकार के बैंकों को अनुशासित किया जाना चाहिए और यदि वे अनुशासन नहीं मानते हैं तो उन बैंकों और संस्थाओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तमाम बैंकिंग लेन–देन पर कर भी प्रस्तावित किया गया है और यह मददगार साबित हो सकता है। इस प्रकार यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हालांकि इन टैक्स हेवन क्षेत्रों के संप्रभु अधिकारों का मुद्दा महत्त्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन अधिकारों के प्रयोग से दूसरे देशों के संप्रभु अधिकारों का हनन होता है और व्यापक रूप से विकास की गति अवरुद्ध होती है। आज के उदारीकृत विश्व में जहाँ पूंजी का सीमाओं से परे निर्बाध विचरण होता है, हमें बाजार निपुणता और नियमन, अंतर्राष्ट्रीय कर योजना और अपराधीकरण से जुड़े वैचारिक और व्यावहारिक मुद्दों को देखने की आवश्यकता है।

<u>शब्दावली</u>

AML- एन्टी मनी लांडरिंग

ATF- दी ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबेको, फायरआर्म्स एक्स्प्लोसिव यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अधीन कानून लागू करने वाला एक संगठन

FATF- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फॉर्स (1989 में) स्थापित इंटरगवर्नमेंटल संगठन है, जो जी–7 देशों की पहल पर बनाया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य मनी लांडरिंग को रोकना था।

FEMA (Foreign Exchange Management Act 1999) – भारत में विदेशी विनिमय को नियमित करने वाले कानून के संशोधन के लिए इस अधिनियम को लाया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा विदेशी विनिमय कानून को विदेशी व्यापार, भुगतान और व्यवस्थित विकास को बढावा देने तथा भारत में विदेशी विनिमय बाजार के प्रबंधन के अनुकूल बनाना है।

FII- FDI के विपरीत, FII अप्रत्यक्ष रूप से स्टॉक और सेक्युरीटिज में निवेश करती है। साधारण शब्दों में ये छोटे स्तर पर निवेश करते हैं।

FinCEN- यह अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेज़री के अंतर्गत एक ब्यूरो है. इसका

उद्देश्य वित्तीय खुफिया कार्रवाइयों और वित्तीय अधिकारियों की रणनीतिक मदद से वित्त व्यवस्था के गैरकानूनी संचालन को रोककर इसकी सुरक्षा करना है।

GFI- Global Financial Integrity वाशिंगटन डीसी में स्थित एक नॉन–प्रोफिट, शोध संस्थान है।

ICJ- International Court of Justice

KYC (Know your customer): बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए काम में लिया जाने वाला शब्द।

Mis-invoicing- जब सीमापार का व्यापार होता है, तो कई बार अधिकृत लोगों को गलत बिल दिए जा सकते हैं। प्रायः आयात का बिल ज्यादा बताया जाता है और निर्यात का कम, जिससे धन बाहर निकल सके।

MNC: Multi National Corporation या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जिनकी उत्पादन इकाइयाँ एक से ज़्यादा देशों में होती हैं।

PMLA- भारत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट 2002 में बनाया गया। इसे मनीलांडरिंग और मनीलांडरिंग से अर्जित किए जाने वाले धन से निपटने के लिए बनाया गया। इस कानून में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनी लांडरिंग में शामिल व्यक्ति के लिए तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

Sparbuch- ये बचत खाते होते हैं और आस्ट्रिया और इसके पडोसी देशों में प्रचलन में हैं। इन्हें खोलने के लिए किसी नाम या पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। जमा और निकासी Sparbuch की पुस्तिका/पासबुक में दर्ज किया जाती है। जिसके पास यह पुस्तिका/पासबुक (और इसका कोडवर्ड) होता है, उसे ही उस खाते का वैध खाताधारक माना जाता है।

TJI- Tax Justice International, see TJN

TJN- Tax Justice Network शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप है जो टैक्स बचाने, टैक्स प्रतिस्पर्धा और टैक्स हेवन के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करते हैं।

USB- USB AG एक स्विस ग्लोबल फाइनेसिंग कंपनी है, जिसके मुख्य कार्यालय बासेल, ज्यूरिख और स्विटजरलैण्ड में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक कार्पोरेशन (International Business Corporation)– ये प्रायः टैक्स हेवन में पंजीकृत होते हैं। ये सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के लिए बनाए जाते है। इनमें बहुत कम व्यवधान होते है। आंतरिक दस्तावेजों और पंजीयनों को क्रम से रखने के कारण इन्हें सार्वजनिक फाइल में कोई वित्त रिपोर्ट नहीं देनीहोती है। इनमें ऑडिट भी आवश्यक नहीं है।

अज्ञात खाता (Anonymous Account)– जहाँ पर वित्तीय संस्थान (बैंक आदि) के पास खाताधारक की पहचान का कोई रिकार्ड नहीं होता है।

आतंकवाद की आर्थिक व्यवस्था– आतंकवादी संगठनों की आय विभिन्न स्रोतों, कानूनी और गैर–कानूनी दोनों से आती है और कई बार इसमें शामिल लोग उस आय के अवैध स्रोत के बारे में नहीं जानते हैं।

ऑफशॉर कंपनी– ऑफशॉर कंपनी टैक्स हेवन या ऑफशॉर वित्त केन्द्रों में स्थापित कंपनी है। यह वैध होती है और विशेष कानून से संरक्षित भी होती है। इन कानूनों से टैक्स में आंशिक या पूर्ण छूट मिलती है।

ऑफशॉर कन्सलटन्ट्स– ये ऐसे लोग हैं, जिन्हें विदेशी बाज़ार की विशेष समझ होती है और अपने ग्राहकों को आवश्यक परामर्श देते हैं।

ऑफशॉर बैंक– ये बैंक भौतिक रूप से मौजूद हों, यह ज़रूरी नहीं है। ये विदेशी या प्रवासी ग्राहकों की वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ऑफशॉर वित्त केन्द्र– ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ कर राहत, गोपनीयता और निवेशक के मनचाहे नियम बनाकर निवेश और व्यापार को आकर्षित काने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गये हैं।

कोकिन– कोका के पेड़ से बनने वाला एक नशीला पदार्थ

क्रेडिट स्विस (Credit Suisse)– क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी एक स्विटज़रलैण्ड की आर्थिक क्षेत्र की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। अन्य वित्तीय सेवाओं के साथ यह क्रेडिट स्विस बैंक भी चलाती है।

गलत मूल्यीकरण (Mis-Pricing)– किसी व्यक्ति या कंपनी का लाभ बढ़ाने के लिए गलत मूल्य बताना।

जनसंहार पीड़ित– नाजियों ने कमतर और खतरनाक कहते हुए कई लोगों का कत्लेआम कर दिया था।

टैक्स हेवन– ऐसा देश या क्षेत्र जहाँ विदेशी लोगों के लिए कम कर या शून्य कर है, गोपनीयता की गारण्टी है, निवेशकों और जमाकर्ताओं के लिए अनुकूल माहौल है। वे सरकारों के बीच टैक्स प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पैदा कर देते है।

ट्रस्ट/संस्था बनाना– ट्रस्ट या संस्था या फाउंडेशन ऐसी इकाइयाँ हैं, जिन्हें कर बचाने के लिए इनके लाभार्थियों के मालिकाना हक और पहचान को छुपाने के लिए बनाया जाता है। ये संपदा के मालिकाना हक को उसके मूल मालिक से अलगाती है। ये इकाइयाँ मालिक द्वारा नियुक्त किए गए ट्रस्टी लोगों के अधीन होती हैं, वह मालिक ट्रस्ट के कानूनी कार्यों के प्रति जवाबदेह होता है, जो लाभार्थियों के संपदा में हिस्से को कैसे रखा जाय के बारे में निर्देश होते हैं।

धन प्रबंधन (Wealth Management)– ये सेवाएँ वित्तीय/निवेश संबंधी सलाह का संयोजन हैं, जिनमें फीस लेकर खातों, कर योजनाओं और कानून या संपदा योजना पर सलाह शामिल हो/नहीं हो सकती हैं।

नंबर्ड अकाउंट– ग्राहक की पहचान छिपाने के लिए बैंक द्वारा दिया गया एक नंबर या कोड।

नाज़ी (Nazi)– 20 वीं शताब्दी के जर्मनी की एक विचारधारा और संगठन, जो रेसिज्म को मानती थी।

पर्सनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग– ये बैंक अंडरराइटिंग और कंपनियों के लिए धन जुटाने से लेकर विलय करवाने तक की कई सेवाएँ देते हैं। ये विभिन्न भूमिकाओं में अनेक काम करते हैं जैसे किसी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए निवेशक और दूसरे पक्ष के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना।

पेट्रिएट एक्ट– 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद 2001 में यूएसए पेट्रिएट एक्ट पारित किया गया। इसका पूरा नाम है– USA PATRIOT- Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept

and Obstruct Terrorism act of 2001. इसका उद्देश्य देश में आंतकवादी गतिविधियों की पहचान और उनकी रोकथाम था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)– एक देश के व्यक्ति या कंपनियों द्वारा किसी अन्य देश में प्रत्यक्ष उत्पादन में सक्रिय निवेश करना या मौजूदा व्यवसाय में नई इकाइयाँ बनाना है।

फर्डिनेंड मार्कोस– इसका पूरा नाम फर्डिनेंड इमेनुल एड्रेलीन मार्कोस था। यह 21 वर्षों (1965–1986) तक फीलिपीन्स का राष्ट्रपति था। पेशे से वह वकील था। इसके अलावा वह 10 साल (1949.1959) तक फीलिपीन्स के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटीव का सदस्य और 6 वर्षों (1959–65) तक सीनेट का सदस्य था। वह 1963 से 1965 तक सीनेट का अध्यक्ष भी था। जब वह सत्ता में था तो उसने ढांचागत और आर्थिक सुधार किए लेकिन उसका प्रशासन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, तानाशाही, भाई–भतीजावाद, राजनीतिक दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बदनाम था। मार्कोस और उसके साथी पर कई भ्रष्ट तरीकों से 5–10 अरब अमरीकी डॉलर अवैध संपति रखने का आरोप था।

राउंड ट्रिपिंग– यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश में कमाए गए अवैध धन को वैध बनाकर स्विस बैंकिंग सिस्टम की मदद से डबल टेक्सेशन ट्रीटी वाले देशों में वैध निवेश के रूप में वापस लाया जा सकता है।

वायर ट्रांसफर सिस्टम (Wire Transfer System)– धन का इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर जिसे दुनियाभर के कई बैंक प्रशासित करते है। इसके द्वारा किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था को धन भेजा जा सकता है और इसमें जल्दी और सुरक्षित स्थानांतरण कुशलता से होता है।

शेल कंपनी/ऑफ दी शेल्फ (Shell Company/Off the Shelf)– ये कंपनियाँ कानूनन पंजीकृत होती हैं। इन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा लंबी इनकोर्पोरेशन प्रक्रियाओं से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

शेल बैंक– शेल बैंक का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है हालांकि ये बैंक समस्त आवश्यक कानूनी शर्ते पूरी करते हैं।

संपति (संपदा) योजना (Estate Planning)– संपदा वह प्रोपर्टी होती है, जो किसी को वंशानुगत मिलती है। संपदा योजना किसी के जीवन में किसी संपति को

उससे अलग करने की योजना होती है। संपदा योजना किसी भी संभावित संपति के प्रबंधन संबंधी अनिश्चितता समाप्त कर देती है और टैक्स तथा अन्य खर्चे कम कर संपदा की कीमत बढ़ा देती है।

सानी अबाचा– जनरल सानी अबाचा नाईजीरिया का एक सैनिक था। बाद में वह राजनीति में आया और पाँच साल तक नाईजीरिया का राष्ट्रपति रहा। अबाचा नाईजीरिया के इतिहास का सबसे ज़्यादा विवादास्पद नेता था। हालांकि उसके समय नाईजीरिया की अर्थव्यवस्था में नाटकीय चढ़ाव आया लेकिन लोगों को परेशानियाँ हुई, मानवाधिकारों का हनन हुआ। अबाचा, उसके परिवार और साथियों ने अपने गरीब देश की 4 अरब अमरीकी डॉलर हड़पने का आरोप है।

स्मर्फिंग– मनीलांडरिंग की प्रक्रिया के पहले चरण प्लेसमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक। इसमें धन को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे वह वित नियमन व्यवस्था की सीमा से कम रहता है।

संदर्भ

Alexander, R. (2013). Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.

Baker, Raymond W. (2005). Capitalism's Achilles Heel: Dirty money and how to renew the free market system. London: John Wiley and Sons.

Block, A.A., Weaver, C.A. and Weaver, C. (2004). All is clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering and International Organized Crime. New York: Greenwood Publishing Group.

Bennett, C.M., and Turner, C.D. (2012). Money Laundering: An Analysis of Federal Law. New York: Nova Science Publishers.

Bowden, S. (1997). Money Laundering: Key Issue and Possible Action. Mimeo: Commonwealth Secretariat.

Chattopadhyay, S. (2005). Measuring the Size of the Underground Economy: A Critique of the MIMIC Approach. Bharatiya Samajik Chintan. Indian Social Science Academy. pp. 57-68

Deneault, Alain (2011). Offshore: Tax Havens and the role of Global Crime. New York: The New Press.

Durieu, R. (2013). Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law: Towards a New Global Legal Order. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Epstein, G.A. (2005). Capital Flight and Capital Controls in Developing Countries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Savona, E. (2000). Responding to Money Laundering: International Perspective. Australia: Psychology Press.

Ferragut, S. (2007). A Silent Nightmare: The Bottom Line and the

Challenge of Illicit Drugs. Canada: Lulu.com publisher

Gallant, M.M. (2005). Money Laundering and the Proceeds of Crime: Economic Crime and Civil Remedies. UK: Edward Elgar Publishing.

Gravelle, Jane G. (2013). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. Congressional Research Service (CRS) Report for Congress. Prepared by Members and Committee of Congress.

Hadnum, L. (2014). The Word's Best Tax Havens (Offshore Tax Series), 9th Ed. UK: Taxcafe UK Limited.

Joshi, M.S. (2005). Occupational Frauds and Money Laundering. Mumbai: Snow White Publications.

Ka D. and Smith, D.C. (2008). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2006. Washington, DC: Global Financial Integrity.

Kar, D. (2010). The Drivers and Dynamics of Illicit Financial Flows from India: 1948-2008. Washington, DC: Global Financial Integrity.

Kar, D. and Curcio, K. (2011). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009 Update with a Focus on Asia. Washington DC: Global Financial Integrity.

Kar, D. (2012). Measuring Illegal Outflows- A Rejoinder. Economic and Political Weekly, Vol. XLVII. No. 51. pp. 75-76.

Koh, J.M. (2006). Suppressing Terrorist Financing and Money Laundering. Seoul: Springer Publisher.

Kumar, A. (1999). The Black Economy in India. New Delhi: Penguin (India).

Kumar, A. (2014). Getting Money Back. Interview in Frontline, June 27.

Kumar, A. (2013). Illegal Flows in India's BOP Accounts: Its

Components and Impact on the Economy. In Dasgupa, B. (Ed.). External Dimension of an Emerging Economy. Essay in honour of Sunanda Sen. London: Routledge. ISBN: 978-0-415-53501-4. pp. 28-43.

Kumar, A. (2012). Measuring Illegal Outflow from the Indian Economy: Some Methodological Issues. Economic and Political Weekly. Vol. XLVII No. 39. pp. 71-74.

Kumar, A. (2012). Bringing back what is ours. The Hindu, March 14.

Kumar, A. (2009). Swiss Bank Accounts: Need to do more to get the money back. The Tribune. August 28.

Kumar, A. (2009). The Satyam Saga: There are other business fraud also. The Tribune, January 24.

Kumar, A. (2005). India's Black Economy: The Macroeconomic Implications. South Asia: Journal of South Asian Studies. Vol. 28. No. 2 pp 249-263.

Lilley, P. (2006). Dirty Dealing: The untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism. London: Kogan Page Publishers.

Masciandaro, D. And Takats, E and Unger, B. (2007). Black Finance: The Economics of Money Laundering. London: Edward Elgar Publishing.

Madinger, J. (2012). Money Laundering: A Guide for Criminal Investigator. 3rd Ed. CRC Press.

Meie, H.B, Marthinsen, J.E. and Gantenbein, P.A. (2013). Swiss Finance: Capital Markets, Banking and the Swiss Value Chain. New Jersey: John Wiley &Sons.

Masciandaro, M. (2004). Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering, and offshore Centre. Burlington: Ashagate Publishing,

Ltd.

Mugarura, N. (2012). The Global Anti-money Laundering Regulatory Landscape in Less Developed Countries. London: Ashgate Publishing.

OECD, Assian Development Bank. (2007). ADB/OECD Anti-Corruption Policies in Asia and the Pacific: Legal and Institutional Reform in 25 Countries. OECD Publishing.

Palmer, H. (2001). Trade Finance Risk: Documentary Fraud and Money Laundering. London: Euromoney Institutional Investor PLC.

Reuter, P., and Truman, E.M. (2004). Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering. Washington, DC: Institute for International Economics.

Reuter, P., Mac Coun, RJ. (2001). Drug War Heresies: Learning from other Vices, Times and Places. Cambridge: Cambridge University Press.

Reuter, P. (2004). The Organization of Illegal Markets: An Economic Analysis: Honolulu: University Press of the Pacific.

Savla, S. (2001). Money Laundering and Financial Intermediaries. US: Kluwer Law International.

Shaxon, N. (2012). Treasure Islands: Tax Havens and the men who stole the world. London: Vintage Books.

Unger, B. and Busuioc, E.M. (2007). The Scale and Impacts of Money Laundering. Cheltnham: Edward Elgar Publisher.

Wolfe, G. (2013). International Tax Evasion & Money Laundering. Los Angeles: B.G. Digital Publisher.

Zhu, M. (2013). The IMF and Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism. IMF Fact Sheet.

मूल्यः 50 रुपये